

आर्थिक परिदृश्य और नीतिगत चुनौतियां

01

अध्याय

समष्टि स्तरीय आर्थिक स्थिरता के शानदार परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष दो बड़ी आन्तरिक नीतियां भी उभर कर आयी हैं : एक तो व्यापक परिवर्तनकारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने का रास्ता साफ करने वाले संविधान संशोधन का संसद में पारित होना, तथा दूसरी बड़ी नीति दो उच्चतम मूल्य वाले नोटों (रु. 500 तथा रु. 1000) का विमुद्रीकरण का निर्णय रही। जीएसटी समूचे देश को एक बाजार का रूप प्रदान करेगा, कर अनुपालन और शासन में सुधार लाएगा तथा निवेश और संवृद्धि को बढ़ावा देगा। यह भारत की सहकारी संघवाद की शासन प्रणाली में एक बड़ा अभिनव प्रयोग भी है। विमुद्रीकरण की कुछ अल्पकालिक लागतें रही हैं, किन्तु इसमें अनेक दीर्घकालिक लाभों की संभावनाएं भी भरी हैं। अब अगले कदमों में लागतों को न्यूनतम और लाभों को अधिकतम करने के लिए आवश्यक उपायों में सम्मिलित हैं : तेजी से, मांग अनुसार, पुनः मुद्रीकरण, आगे कर सुधार (जो भू एवं भवन संपदाओं के लेनदेन को जीएसटी के प्रभाव क्षेत्र में लाएं), कर दरों और स्टेप शुल्कों में कमी, तथा कर प्रशासकों के अतिउत्साह को लेकर फैली हुई चिन्ताओं का निराकरण करना। ये कदम 2017-18 में एक बार फिर से अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर को अपने सामान्य प्रवृत्ति पथ पर ले आएगा। वर्ष 2016-17 में आयी शिथिलता एक अस्थायी विचलन बन कर रह जाएगी। यदि और दूर तक भविष्य में झांकने का प्रयास करें तो तो लगता है तीन दीर्घ काल से चली आ रही विराट चुनौतियों- दक्षताहीन पुनःवितरण, निजी क्षेत्र एवं संपदाधिकारों के प्रति दुलमुल व्यवहार और अभी तक त्रुटिपूर्ण रही प्रशासकीय क्षमताओं के उन्नयन का सामना करने के लिए सामाजिक विचारों और संवाद के स्तर पर बड़े परिवर्तनों की आवश्यकता अपरिहार्य होती जा रही है। विमुद्रीकरण के पश्चात् और वैश्वीकरण से घिर रही निराशा के संदर्भ में तो लगता है इन वैचारिक परिवर्तनों को सुबद्ध स्वरूप प्रदान कर इन्हें अपना लेना यह सुनिश्चित करने में निर्णायक सिद्ध होगा कि भारत का उत्कर्ष एक चिरधारणीय विकास है, क्षण भंगुर नहीं।

I. विषय प्रवेश

1.1 आर्थिक समीक्षा 2014-15 ने भारत की अर्थव्यवस्था के ऐसे उत्कर्ष आरंभ बिन्दु की बात की थी जहां से देश 8-10 प्रतिशत की निरंतर धारणीय दर से संवृद्धि के प्रक्षेप पथ पर प्रगति कर सकता है। पिछली वार्षिक समीक्षा ने भी आग्रह किया था कि वह उत्कर्ष आरंभ बिन्दु अभी भी देश को आमंत्रित कर रहा है, किन्तु संभवतः सदैव ऐसा आमंत्रण नहीं मिल पाए। इस वर्ष की जांच पड़ताल सुझा रही है कि आने वाली बड़ी चुनौतियों पर पार पाने और संवृद्धि दर को

तीव्र करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय पाने (अध्याय-2, यही समीक्षा) के लिए समाज के अर्थ चिन्तन की धारा में बदलाव लाने आवश्यक होंगे। विमुद्रीकरण के बाद, और चक्रीय विकास क्रम से आर्थिक प्रबंधन में संभावित कठिनाइयों की आशंका के कारण उन बदलावों का स्पष्ट निरूपण कर उन्हें अंगीकार कर लेना उक्त उत्कर्ष बिन्दु को चिरस्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगा।

1.2 इस वर्ष में आर्थिक नीति के पटल पर अनेक ऐतिहासिक विकास हुए हैं। आन्तरिक स्तर पर तो संविधान

संशोधन ने दीर्घ प्रतीक्षित युग परिवर्तनकारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का मार्ग प्रशस्त किया है, तो बड़े मूल्यमान के नोटों के विमुद्रीकरण ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब गैर कानूनी गतिविधियों की लागत दंडात्मक स्तरों तक उच्च होने जा रही है। अंतराष्ट्रीय पटल पर ब्रेक्जिट-ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से निकासी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के महानिर्वाचन भी इतनी बड़ी उथल-पुथल रहे हैं, जिनसे विश्व अर्थव्यवस्था पर कलिमापूर्ण आशंकाओं की छाया मंडराने लगी है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इन छायाओं से पूर्णतः निरापद नहीं रह पाएगी।

1.3 आइए विमुद्रीकरण से चर्चा आरंभ करें। नवंबर 8, 2016 की सांय यह क्रांतिकारी प्रशासकीय एवं सामाजिक अभियांत्रिकी पूर्ण कदम उठाया गया। देश की समस्त मुद्रा आपूर्ति के 86 प्रतिशत अंश, एक हजार और पाँच सौ रूपयों के करैसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। वे कुछ एक कार्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के लेनदेनों के लिए विधि संगत नहीं रहे।¹ इन्हें दिसंबर 30 तक किसी न किसी बैंक में जमा कराया जाना था, साथ ही बैंकों से नकद निकासी पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। दूसरे शब्दों में देशीय मुद्रा और बैंक खातों की नकदी में परिवर्तनशीलता पर कुछ सीमाएं लागू कर दी गईं।

1.4 इस कार्य के चार उद्देश्य थे : भ्रष्टाचार, नकली नोट छापने, उच्च मूल्य के नोटों के सहारे आतंकवाद फैलाने और कर अधिकारियों के समक्ष अघोषित काली कमाई से कालेधन के संकलन पर नियंत्रण लगाना। यह बड़ा कदम अनायास ही नहीं उठा लिया गया था। ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में पहले से ही कई कदम उठाए जा रहे थे, जैसे कि 2014 के बजट में ही विशेष जांच दल का गठन; कालाधन अधिनियम, 2015; बेनामी लेनदेन अधिनियम, 2016; स्विटजरलैंड के साथ जानकारी सांझा करने का समझौता; मॉरिशस और साइप्रस के साथ नई कराधन संधियां; तथा अघोषित आय घोषणा योजना।

1.5 विमुद्रीकरण का ध्येय एक व्यवस्था परिवर्तन की

घोषणा था। इसमें धन से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियों को दंडित करने के प्रति सरकार के आग्रह की स्पष्टोक्ति भरी थी। वास्तव में गैर कानूनी और कानूनी कराधिकारियों के समक्ष अघोषित गतिविधियों पर करों की दर को दण्डात्मक स्तर तक पहुँचाने का मन्तव्य स्पष्ट किया जा रहा था।

1.6 विमुद्रीकरण पर सार्वजनिक विमर्श में तीन प्रश्न उभर कर आए हैं। पहला प्रबंधन के आयामों से जुड़ा व्यापक प्रश्न इस नीति प्रयास की रचना और क्रियान्वयन विधि से जुड़ा है; दूसरा प्रश्न इसके अल्प एवं दीर्घकालिक प्रभावों से संबंधित है; और तीसरा प्रश्न आर्थिक नीतियों के भावी संचालन के आधारिक दर्शन के लिए निहितार्थों से भरा है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा करने के लिए वर्तमान समीक्षा एक उचित पटल नहीं होगा।

1.7 अध्याय-3 में दूसरे प्रश्न पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। वहां हमारा मुख्य निष्कर्ष यही है कि विमुद्रीकरण की कुछ अल्पकालिक लागतें अवश्य हमें भुगतनी होंगी किन्तु यह कदम दीर्घकालिक हित एवं लाभों का आधार निर्मित करेगा।

1.8 अल्पकालिक लागतों ने असुविधा और कठिनाइयों का रूप धारण किया है। यह समाज के अनौपचारिक और नकदी का ही प्रयोग करने वाले व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिक कष्ट भरी अवधि रही है। यहां एक बड़े जन समुदाय को आय और रोजगार की हानि सहन करनी पड़ी है। ये लागतें बहुत अस्थायी हैं और जीडीपी के आंकड़ों में शायद ही इनकी झलक मिल पाए। कारण यही है कि राष्ट्रीय आय लेखा अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान का आंकलन औपचारिक क्षेत्र के सूचकों के आधार पर ही करता है, और ये इतने दुष्प्रभावित नहीं हुए हैं। किन्तु लागतें वास्तविक रही हैं और महत्वपूर्ण भी। निम्न ब्याज दरों तथा कीमतों में आई कुछ कमी ने भी अल्पकाल में समष्टि स्तरीय प्रभावों को कुछ संयत रखा है।

1.9 फिर भी विमुद्रीकरण में निम्न भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के उच्च स्तर पर डिजिटाइजेशन, वित्तीय बचतों के बेहतर प्रवाहों, और अर्थव्यवस्था के अधिक

¹ सही अर्थों में केवल पानी, बिजली आदि के भुगतान के अतिरिक्त नोट कागज के टुकड़े बन कर रह गए थे। फिर भी आम आदमी के लिए नवंबर 8 की घोषणा ही विमुद्रीकरण का स्थूल रूप धारण कर गई है।

उच्च स्तर पर औपचारिकरण के माध्यम से दीर्घकालिक हित लाभों के सृजन की व्यापक संभावनाएँ हैं। ये सभी कार्य जीडीपी में वृद्धि के साथ-साथ बेहतर स्तर पर अनुपालन तथा अधिक कर राजस्व संकलन में सहायक होंगे।

1.10 दीर्घकालिक लाभों के समय एवं वित्त की ही भाँति अल्पकालिक लागतों के परिमाण को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। (अध्याय-3 में लाभों के आंकलन हेतु प्रयोज्य कुछ संकेतकों की चर्चा की गई है)। ये सभी परिमाण इस बात पर भी निर्भर रहेंगे कि नीति स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों को किस प्रकार समझ कर उचित कदम उठाए जाते हैं। अभी आवश्यक प्रतीत हो रहे कार्य हैं : आवश्यक नकदी की आपूर्ति कर यथाशीघ्र अर्थतंत्र का पुनःमुद्रीकरण करना (विशेषकर निम्न मूल्यमान के नोटों की आपूर्ति बढ़ाना) और विमुद्रीकरण के संपूरक प्रायः कदम उठाना। ये हैं भूमि और संपदा को जीएसटी के प्रभाव क्षेत्र में लाना, कर और स्टैप शुल्क घटाना तथा ध्यान रखना कि प्रशासक विमुद्रीकरण के बाद अधिक अतिसक्रिय नहीं हो जाएं।

1.11 व्यापक जीवन दृष्टि से जुड़ा तीसरा प्रश्न भी अर्थव्यवस्था के विकास के मध्यम अवधि पथ का निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यहां सरकार ने पिछले वर्ष कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम तो युग परिवर्तनकारी जीएसटी विधेयक रहा है जो सारे देश को एक सुगठित बाजार बनाने, कर अनुपालन बढ़ाने, निवेश एवं संवृद्धि को बढ़ावा देने, सामान्य प्रशासन को सुधारने के साथ-साथ सहकारी संघवादी शासन व्यवस्था के संचालन में भी एक नवीन साहसपूर्ण प्रयोग सिद्ध होगा। साथ ही सरकार ने ये कार्य भी किए हैं :

- दीवालियापन संबंधी कानूनों की पुनः रचना, ताकि पिछली समीक्षा में बताए गए उन हानि कर प्रभावों का शीघ्रान्तिशीघ्र निराकरण हो सके जो अर्थव्यवस्था के प्रगति पथ में बाधक बन रहे थे;
- रिजर्व बैंक के साथ मिलकर मौद्रिक नीति पर संस्थागत संरचनाओं को सूत्रबद्ध करना ताकि व्यक्तियों और सरकार के मनमाने व्यवहार से स्फीति नियंत्रण नीतियों को मुक्ति दिला कर समष्टि आर्थिक

स्थिरता के लाभों को और बढ़ाया जा सके; और

- “आधार” के विधिक आधार को अधिक बल प्रदान कर जाम (जनधन-आधार-मोबाइल) की पिछली समीक्षा में चर्चित त्रिविध-युक्ति-युति को प्रभावी रूप प्रदान करना।

1.12 यदि ऐसी कार्यसूची की सरकार ने 2016 के आरंभ में घोषणा की होती तो निश्चित रूप से इस पर अविश्वास ही होता। किन्तु एक वर्ष में ही यह सभी कार्य संभव हो गए हैं, वह भी प्रायः राजनीतिक सर्वानुमति के सहारे विधायी प्रयासों के माध्यम से।

1.13 इन बहुचर्चित बड़े सुधारों के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे किन्तु दूरगामी संभावनाओं से परिपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने वस्त्र-परिधान क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के ध्येय से कई कदमों वाला एक समुच्चय (पैकेज) घोषित किया है। यह कदम इस निर्यातानुमुखी उद्योग को बढ़ावा देगा, बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा और वह भी महिलाओं के लिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने एकीकृत भुगतान पटल (UPI-यूपीआई) को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है। यह विभिन्न सेवातंत्रों पर समान रूप से कार्य करने वाली व्यवस्था भुगतान के डिजिटलीकरण और वित्तीय समाहन को प्रभावी बनाने में मोबाइल फोन की वास्तविक क्षमताओं को प्रभावी रूप प्रदान पर उपर्युक्त चर्चित ‘JAM’ (जनधन, आधार-मोबाइल) के मोबाइल घटक को सरकार के प्रशासन तंत्र की एक आधारिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) व्यवस्था में अनेक सुधार लागू कर भारत को विदेशी निवेश पाने वाले सबसे बड़े देशों की पंक्ति में भी शामिल किया गया है।

1.14 इन सभी कदमों ने विश्व के धूमिल पड़े आर्थिक मंडल में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते हुए सितारे की आभा प्रदान की है। अब भारत केवल तीव्रतम संवृद्धिमान बड़े देशों में से एक नहीं रह गया है, जहां स्फीति में कमी आ रही है, राजकोषीय एवं बाह्य संतुलनों में सुधार हो रहा है- यह उन इने गिने देशों में भी सम्मिलित है, जिन्होंने बड़े संरचनात्मक सुधार भी किए हैं। किन्तु अभी भी समष्टि आर्थिक स्थिरता एवं

संवृद्धि की इस वास्तविकता तथा क्रम निर्धारक संस्थानों के चिन्तन में एक अन्तर दिखाई दे रहा है। इस अंतर

के संभावित कारणों पर बॉक्स-1 में विस्तार से व्याख्या की गई है।

बॉक्स-1 : त्रुटिपूर्ण मानक? क्रमनिर्धारक संस्थाएं, चीन एवं भारत

पिछले कुछ वर्षों से क्रमनिर्धारक संस्थाओं की भूमिका पर बार-बार प्रश्न उठने लगे हैं। संयुक्त राज्य के वित्तीय संकट के समय बंधक आधारित निक्षेपों को AAA घोषित करने में उनकी भूमिका को लेकर बड़े प्रश्न उठे थे, क्योंकि उनकी आधारभूत परिसंपत्तियां स्वयं ही 'विश्राक्त' थीं (इसका माइकल लुइस ने अपनी रचना 'द बिग शॉर्ट' में वर्णन किया है)। साथ ही किसी वित्तीय संकट की आशंका का पूर्वाकलन कर पाने में किलता ने भी उन संस्थाओं के महत्व पर उंगली उठाई है। प्रायः किसी की भी क्रमिकता को घटना घटित होने के बाद ही कम किया गया है। दूसरे शब्दों में घोड़ों के भाग जाने के बाद ही अस्तवल के दरवाजे बंद किए गए हैं (IMF, 2010, क्रूमैन, सितंबर, 2015²)।

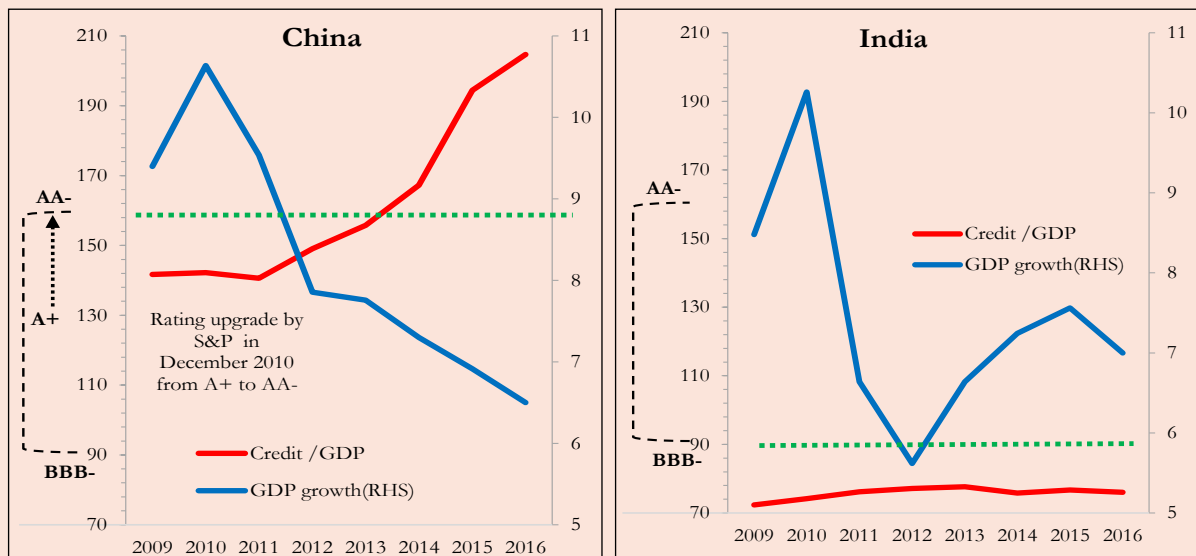
किन्तु अधिक सामान्य स्थिति में भी उनकी भूमिका के मूल्यांकन पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत के संदर्भ में नवंबर 2016 में स्टैंडर्ड एवं पूअर ने निम्न जीडीपी और उच्च स्फीति के कारण इसकी क्रमिकता में कुछ भी सुधार करने की संभावना से इंकार कर दिया था। इस क्रमिकता तक पहुँचने की वास्तविक गणना अवधि तो कहीं अधिक जटिल होती है, परन्तु यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या भारत द्वारा ऋण चुका पाने की असमर्थता की जोखिम का आकलन केवल इन दो चरों के आधार पर कर लेना सही था?

पहले प्रतिव्यक्ति जीडीपी पर चर्चा करते हैं। यह एक बहुत धीमी गति से चलने वाला चर है। निम्न मध्यम आय वर्ग के देशों में 1970-2015 की अवधि में 2010 के स्थिर डालरों में प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर की औसत 2.45 प्रतिशत रही है। इस दर पर संवृद्धिशील गरीबतम निम्न मध्यम आय वर्ग के देशों को उच्च मध्यम आय वर्ग के स्तर पर पहुँचने में 57 वर्ष लग जाएंगे। यदि यह चर वास्तव में क्रमिकता निर्धारण की सटीक कसौटी है तो क्या गरीब देशों का यह कहना उचित नहीं होगा, "कृपया इस वर्ष कष्ट न उठाएं, हमारी क्रमिकता का आकलन करने के लिए तो अर्द्धशती के बाद आइए"?

अब राजकोषीय चरों पर बात करते हैं : क्रमिकता निर्धारक संस्थाएं प्रायः अनेक देशों के समूह बना कर उनके राजकोषीय चरों के व्यवहार का तुलनात्मक आकलन करती हैं। अतः उदीप्यमान बाजार व्यवस्थाओं के समूह में राजकोषीय घाटा अनुपात 6.6 प्रतिशत (2014) तथा ऋण 67.1 प्रतिशत होने के कारण भारत एक 'बहिष्कायी' घोषित हो जाता है। (देखें तालिका-1, अध्याय-5)।

किन्तु वास्तव में भारत उन देशों से बहुत ही भिन्न हो सकता है, जिनके साथ इन संस्थाओं ने तुलना की है। यह तो सत्य है कि अनेक उदीप्यमान बाजार आज कठिनाइयों में उलझे हुए हैं। किन्तु भारत सतत संवृद्धि पथ पर अग्रसर है और यहां पिछले तीन वर्षों से राजकोषीय अनुशासन की प्रतिबद्धता के दर्शन हुए हैं। इसी से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आगामी वर्षों में यहां घाटा और ऋण अनुपातों में महत्वपूर्ण कमी आना सुनिश्चित है। यह परिदृश्य सत्य नहीं होने पर भी भारत का इतिहास बताता है कि इसने कभी अपने भुगतान दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा है। अतः यह अतिउच्च "भुगतान की तत्परता" वाला देश निश्चित ही कहीं उच्चतर ऋण वहन कर सकता है (Reinhart, Rigoff and Savastano, 2013)।

रेखाचित्र : साख जीडीपी अनुपात और जीडीपी की संवृद्धि : चीन और भारत और S&P द्वारा प्रदान की गई क्रमिकताएं



स्रोत : WDI और S&P 2016 के भारत के साख के आंकड़े RBI और Credit Suisse से 2016 के चीन के आंकड़े सकल सामाजिक वित्तीयन (TSF) के Bank of International Settlements से प्राप्त 2015 के स्टॉक को जोड़कर आंकलित किए गए हैं।

² <http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/09/17/fear-the-rating-agencies/>

भुगतान जोखिम के अन्य मापकों पर भी भारत अन्य देशों से बेहतर सिद्ध होता है। चीन से ही तुलना करें। वर्ष 2009 में चीन ने अपना ऐतिहासिक साख प्रसार प्रारंभ किया था, जो अभी तक साख जीडीपी अनुपात में 63 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि कर चुका है, यह तो भारत के समस्त जीडीपी स्टॉक से कहीं अधिक है (देखें रेखाचित्र)। इसी समय में चीन की संवृद्धि दर भी 10 से घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई है।

तो फिर S&P की इस केंची आकार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही? शेष विश्व तो इसे चीन तथा समूचे संसार के लिए गंभीर आर्थिक संकट की आशंका मान रहा है। दिसंबर 2010 में इसने चीन की क्रमिकता का A+ से AA- तक उन्नयन कर डाला। भले ही उसके बाद से साख में विस्फोटक वृद्धि और संवृद्धि दर में भारी गिरावट आई हो पर S&P ने क्रमिकता में परिवर्तन का कष्ट नहीं उठाया है।

इसके विपरीत, भारत की क्रमिकता को बहुत निम्न स्तर, BBB पर अटकाया हुआ है, भले ही 2014 से संवृद्धि और समष्टि आर्थिक स्थिरता में नाटकीय सुधार हुए हों।

इन विपरीत व्यवहारों के कारण यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि क्या क्रमिकता निर्धारण आर्थिक दृष्टि से सटीक कार्यविधि द्वारा निर्धारित होती भी है?

1.15 किन्तु और बहुत कुछ करना बाकी है। वर्ष 1991 के बाद तो विशेष रूप से भारत अपने आपको “माइबाप सरकारवाद” से दूर हटाता जा रहा है और इसने अपने अर्थप्रबंधन में बहुत बड़े सुधार किए हैं। किन्तु फिर अध्याय-2 में किए गए लेखेजोखे से स्पष्ट है कि संवृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय की अपनी अभिलाषाओं की प्राप्ति हेतु देश को अभी बहुत कुछ करना है। तीन बड़ी चुनौतियां : दक्षताहीन पुनःवितरण में कमी; आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुधारने और बाजारों के नियमन की सरकार की क्षमताओं में वृद्धि तथा संपदाधिकारों की सुरक्षा के प्रति दुलमुलपन त्याग कर बाजार को अंगीकार करने की दिशा में विचार एवं विमर्श तंत्रों में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में इन चुनौतियों का सामना करना मात्र निहितस्वार्थों पर नियंत्रण की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रश्न नहीं है।

1.16 इन संरचनात्मक चुनौतियों के तुल्य नीतिगत कदम भी हैं। अध्याय-9 में भारत के व्यापक पुनःवितरण के प्रयासों की समीक्षा की गई है। केवल केन्द्रीय सरकार ही 950 केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाएं एवं उपयोजनाएं संचालित कर रही है और उन पर जीडीपी के लगभग 5 प्रतिशत अंश का व्यय हो रहा है। स्पष्टतः इनमें से अनेक के लिए तर्काधर विद्यमान है। किन्तु उनके लाभ अपेक्षित हितलाभी वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुँचने को लेकर कुछ संदेह बने रहते हैं। अर्थात् उनकी ‘लक्षिता’ को लेकर अन्तर्भूत सीमाएं या त्रुटियां भी बनी हुई हैं।

1.17 पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने पुनःवितरण तंत्र की दक्षता को सुधारने की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति

की है। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सम्मिलित हैं आधार कानून पारित करना—जो JAM के लक्ष्य की सिद्धि की ओर एक बड़ा कदम है (इसी संदर्भ में उर्वरकों की सब्सिडी को लेकर प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण का प्रयोगात्मक प्रकल्प एक बहुत ही नई दिशा की ओर संकेत कर रहा है)। साथ ही अनेक क्षेत्रों में उपभोक्ता द्वारा देय कीमतें अभी बाजार कीमतों के निकट पहुँचनी बाकी है। जीएसटी को लेकर भी आवश्यक वस्तुओं/पदार्थों पर करों की दर को न्यून बनाए रखना और (वह भी अनेक अति उच्च दरों वाली जटिल कर रचना का निर्माण किए बिना, जिससे दीर्घकालिक सेवा दक्षता कुंठित हो सकती है) अपने आप में एक चुनौती है।

1.18 अब राज्यों की क्षमताओं की बात पर आते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आवश्यक सेवाएं मुख्यतः प्रांतीय सरकारों के अधिकार-दायित्व क्षेत्र का अंश है और इनकी आपूर्ति अभी त्रुटिपूर्ण ही बनी हुई है। नियामक संस्थान अभी अपनी राह खोजने में लगे हैं। यहां सबसे गहन समस्या तो यह है : निवेश एवं प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के बीच स्पर्धापूर्ण संघवाद बहुत ही उत्कृष्ट एवं मुखर दिखाई देता है, किन्तु आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के मामले में यह स्पर्धा बहुत क्षीण रह जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी रहे हैं— जैसे कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, मध्य प्रदेश में कृषि में संप्रेरणों का संचार, गुजरात में विद्युत क्षेत्र के सुधार (जिनसे आपूर्ति और लागत की उगाही में सुधार हुए हैं), तमिलनाडु में सामाजिक कार्यों की दक्षता वृद्धि और अभी हाल ही में हरियाणा को ‘घासलेट मुक्त’ बनाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि। किन्तु स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे

प्रतिमान नहीं उभर पाए है, जिनका देश भर में प्रसार हो सके और जिन्हें अपना आकर्षक राजनीतिक सुअवसरों का रूप धारण कर सके। स्पर्धी लोक लुभावन का स्पर्धी सार्वजनिक सेवा प्रदाय स्वरूप भी होना ही चाहिए।

1.19 इसी प्रकार अनेक दशकों से निजी क्षेत्र एवं संपदाधिकारों को लेकर राजनीतिक स्तर पर अस्पष्टता निवारक चिन्तन का कोई सशक्त प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। इस अस्पष्टता के परिणाम हमें यहां दिखाई पड़ते हैं : व्यक्तिगत विनिवेश में; दोहरी तुलनपत्र व्यवस्था जारी रहने में; निगम एवं बैंक क्षेत्र की अतिशय ऋण ग्रस्तता में; जो भार के विभाजन के विषय में फैसले करना कठिन बना देती है (विशेष कर जहां निजी क्षेत्र को कुछ छूट देने की बात हो), पिछली तिथि से कर लागू करने के अधिकार (भले ही इनके कारण सरकार निरंतर न्यायिक मामलों में उलझी रही हो सरकार ने इस विषय में अपना भावी मंतव्य तो स्पष्ट कर दिया है); कृषि, जहां बौद्धिक संपदाधिकार संरक्षण का प्रश्न (बीजों को लेकर) बना हुआ है; नागर विमानन क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता-जहां बार-बार उदारवाद और हस्तक्षेप के उतार-चढ़ाव दिखाई देते हैं; उर्वरक क्षेत्र, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के अत्यंत दक्षताहीन कारखानों का पुनःप्रतिष्ठापन ही उन्हें बंद करने की अपेक्षा अधिक आकर्षक विकल्प प्रतीत होता है; बहुत पुराने पड़ गए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बार-बार कृषि उत्पादों के लिए स्टॉक सीमाओं में फेर-बदल और नियंत्रण किसानों सहित संपूर्ण कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखते हैं।

1.20 भले ही यथास्थिति बनाए रखने के कितने ही 'उचित कारण' हो, ये सभी उदाहरण स्पष्ट समझा रहे हैं कि अगर अधिक गहरे हस्तक्षेपवाद से बचने जितना ही बाजार को अंगीकार कर लिया जाए, संपदाधिकारों का संरक्षण किया जाए, उन सार्वजनिक उपक्रमों से मुक्त पाली जाए जो अर्थक्षम नहीं बचे हैं; तुलनात्मक लाभहीनता के क्षेत्रों से निकला जाए और विभिन्न आर्थिक कर्ताओं को बाजार कीमतों का सामना करने दिया जाए, ये सब नीतिगत उपाय संपूर्ण रूप से अभी अपनाए नहीं गए हैं।

1.21 हमारी आन्तरिक कार्यसूची अभी पूरी नहीं हो पायी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आ रहे बदलाव नई

चुनौतियां प्रस्तुत करने लगे हैं। ब्रेकिंग और अमेरिकी चुनाव परिणाम के प्रभाव अभी अनिश्चित हैं किन्तु इनमें पृथकतावाद एवं स्थानिकतावाद की दिशा में एक संवाद विमर्श स्तरीय अन्तरण की आशंकाएं अवश्यक उभर रही हैं। विश्व भर के उन्नत देशों में अब महायुद्धोपरांत विकसित वस्तुओं और सेवाओं, विशेष कर श्रम शक्ति, संबंधी वैश्वीकरण की आम सहमति और बाजार आधारित आर्थिक संगठन पर आज गंभीर संकट के बादलों की काली छाया मंडराने लगी है।

1.22 भारत, जो एक देर से 'संसृतिपथगामी' बना है, जिसका जीवन स्तर अभी अग्रणी देशों से बहुत निम्न है, के लिए तो यह घटनाचक्र बहुत से प्रभावों से भरा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के 8-10 प्रतिशत दर से संवृद्धि कर पाने की महत्वाकांक्षा की संपूर्ति के लिए निर्यात में निरंतर 15-20 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक होगी। किन्तु भारत के व्यापार सहयोगियों द्वारा निर्बाध व्यापार के पथ से विचलित होने पर तो हमारी संवृद्धि विषयक आकांक्षाएं बहुत खतरे में पड़ जाएंगी (देखें बॉक्स-2)।

1.23 इन आन्तरिक एवं बाहरी संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ ही हमें समष्टि स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। जून 2014 के शिखर स्तर से पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद से आय में उछाल दिखाई दिया है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों ने निजी उपभोग को प्रोत्साहित किया है, सार्वजनिक निवेश का मार्ग सुगम बनाया है, तथा कमजोर विदेशी मांग एवं निम्न आंतरिक कृषि उत्पादन के थपड़े झेल रही अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है। किन्तु इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में फिर उभार आ रहा है तथा इससे हमारी अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक गतिशीलता कुछ कुंठित होने की आशंका है। वर्षों से नासूर की भांति पीड़ा दे रही दोहरी तुलन-पत्र प्रणाली के मारे निजी निवेश में भी शिथिलता दिखाई दे रही है (देखें अध्याय-4)। अब निजी निवेश तथा निर्यात में निरंतर वृद्धि को आर्थिक संवृद्धि के प्रमुख एवं चिरंतन स्रोत के रूप में प्रतिष्ठापित करना एक महती समष्टि आर्थिक चुनौती का रूप धारण कर रहा है।

1.24 कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों से संरचनात्मक

सुधारों की दिशा में किए गए सुधारों को आधार बना उन पर और तीव्र गति से नवनिर्माण करना तथा अभी तक अपूर्ण कार्यों को पूरा करना आवश्यक हो गया है। विमुद्रीकरण के पश्चात् एवं निरंतर प्रस्तुत दीर्घकालिक चुनौतियों के चलते उस उत्कर्ष बिंदु से जुड़े संयोगों को खो बैठने को लेकर उठ रही आशंकाओं का सुनिश्चित रूप से निवारण करना आवश्यक हो गया है।

II. वैश्विक परिप्रेक्ष्य

1.25 तीन बाह्य घटनाक्रम भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अल्पकाल में विश्व भर में ब्याज की दरों का परिदृश्य अमेरिकी चुनावों तथा उसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों विषयक अपेक्षाओं के कारण भारत के पूंजी प्रवाहों और विनिमय दरों को प्रभावित करेगा। बाजार पहले ही उन्नत देशों में सत्तातंत्र में हो रहे परिवर्तनों का आकलन-समंजन करने में लगा है, उसे अमेरिकी समष्टि आर्थिक नीतियों, विशेषकर राजकोषीय प्रोत्साहन और गैरपारंपरिक मौद्रिक नीति से सुनिश्चित रूप से पलायन को लेकर बहुत उत्साहवर्धक आशाएं हैं। बीस वर्षों से निरंतर बाँड कीमतों में उछाल की प्रक्रिया और अवस्फीति एवं अवस्फीतिकारी अपेक्षाओं

के पाश से शीघ्र मुक्ति अब निकट प्रतीत हो रही है।

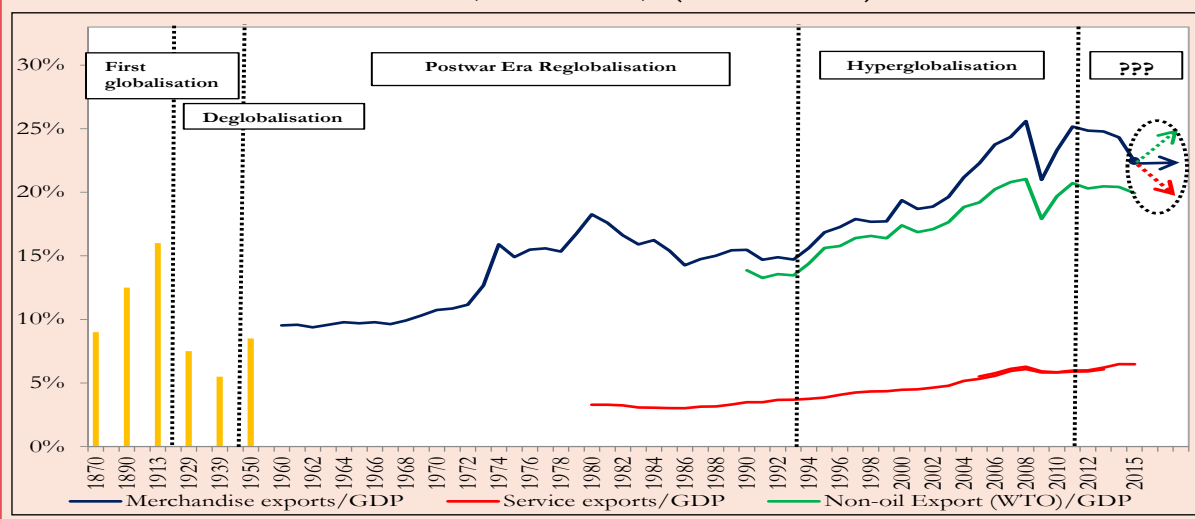
1.26 दूसरे पटल पर वैश्वीकरण विषयक मध्यकालिक राजनीतिक संभावनाओं की बात आती है। अभी-अभी के घटना चक्र ने संभवतः विश्व की “वैश्वीकरण हेतु राजनीतिक धारण क्षमता” को बहुत प्रभावित कर दिया है। अल्पकाल में डालर की सबलता में वृद्धि और स्पर्धाशीलता का हास संरक्षणवादी नीतियों को अति आकर्षक स्वरूप प्रदान कर सकता है। यह पहले ही व्यापक रूप से स्वीकार किए जा रहे रुझानों : शिथिल या हासमान विश्व व्यापार (देखें बॉक्स-2 का रेखाचित्र) के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आ रहा बदलाव बॉक्स-2 में निरूपित भारत की निर्यात एवं संवृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा।

1.27 तीसरा पटल है अमेरिकी घटनाक्रम, डालर की सुदृढ़ता और उनके चीन की मुद्रा एवं विनिमय नीतियों पर प्रभाव का। यदि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित करने में सफल रहता है तो इसके भारत एवं शेष विश्व पर सकारात्मक प्रच्छालन प्रभाव होंगे। दूसरी ओर युवान में हास भले ही डालर के कारण हो, वह चीन में विद्यमान आन्तरिक भेद्यताओं के साथ मिलकर

बॉक्स-2 : पश्चिम की निर्बन्धता विषयक राजनीति धारण क्षमता और भारत पर इसके प्रभाव

कभी टी एस इलियट ने कहा था कि ‘मानवजाति बहुत अधिक वास्तविकता को सहन नहीं कर पाती’ तो हाल ही का घटना चक्र बता रहा है कि विश्व अत्यधिक वैश्वीकरण को भी सहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसका भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव होगा? पहले रेखाचित्र में 1870 से लेकर विश्व के व्यापार जीडीपी अनुपात अंकित किए गए हैं। इसके चार सोपान रेखांकित किए जा रहे हैं। वैश्वीकरण की दो बड़ी लहरें 1870-1914 और 1945-84 की अवधियों में चली थीं, अतिउग्र वैश्वीकरण का ज्वार 1985-2008 के बीच रहा (सुब्रमण्यम एवं केस्लर, 2014) तथा अन्तः महायुद्धकाल में एक अ-वैश्वीकरण का सोपान रहा है। आगे क्या होगा, ये प्रश्न तीन तीरों द्वारा पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार में और आगे वैश्वीकरण होगा, अ-वैश्वीकरण होगा या फिर शैथिल्य का संचार होगा? इन तीनों संभावनाओं के भारत के निर्यात-आयात व्यापार और देश की संवृद्धि दर पर बड़े महती प्रभाव होंगे।

रेखाचित्र : वैश्वीकरण और विश्व (1870 से आजतक)



वर्ष 2003-2011 के उत्कर्षकाल में भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि की औसत दर 8.2 प्रतिशत रही और वास्तविक डालरों में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात की वार्षिक वृद्धि 20 से 25 प्रतिशत के बीच रही। अतः यह मानना उचित ही प्रतीत होता है कि अगले दशक में 8 प्रतिशत दर पर संवृद्धि का लक्ष्य रखने वाले भारत को अपने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 15 प्रतिशत दर पर अवश्य बढ़ाना होगा।

अब यह भी मान लेते हैं कि विश्व भविष्य में 3 प्रतिशत दर से संवृद्धिशील रहेगा। हम विश्व की वैश्वीकरण हेतु राजनीतिक धारण क्षमता को निर्यात जीडीपी अनुपात द्वारा परिभाषित कर रहे हैं। उसका नवीनतम आंकड़ा 21 प्रतिशत है। हम मान लेते हैं कि यह अनुपात भी स्थिर रहेगा (ध्यान रहे कि जैसा पिछले कुछ वर्षों में दिखाई दिया है, यदि व्यापार वृद्धि की दर जीडीपी से पिछड़ जाएगी, तो संतुलन स्तर पर धारण क्षमता अर्थात् विश्व का निर्यात जीडीपी अनुपात वास्तव में कम हो जाएगा।)

निर्बंधता हेतु विश्व की राजनीतिक धारण क्षमता (वर्तमान एवं भावी)

	आज			10 वर्षों में परिवर्तन			
	विश्व	भारत	चीन	विश्व (स्थिर)	भारत	चीन	शेष विश्व नाम प्रायः
विश्व वस्तु निर्यात/विश्व जीडीपी	21.10%	0.40%	2.90%	0.00%	0.80%	1.40%	-2.10%
विश्व सेवा निर्यात/विश्व जीडीपी	6.10%	0.30%	0.40%	0.00%	0.50%	0.20%	-0.70%
वस्तु एवं सेवा निर्यात/विश्व जीडीपी	27.30%	0.60%	3.30%	0.00%	1.30%	1.50%	-2.80%
विश्व जीडीपी संवृद्धि विषयक मान्यताएं : विश्व (3%), भारत (8%), चीन (5%)							
निर्यात संवृद्धि मान्यताएं : विश्व (3%), भारत (15%), चीन (7%)							

स्रोत: समीक्षा की गणनाएं

इन परिस्थितियों में उठने वाली समस्याएं ये हैं : केवल भारत की जीडीपी और निर्यात संवृद्धि विश्व निर्यात-जीडीपी अनुपात में 1.3 प्रतिशत बिन्दुओं को योगदान देगी। पिछले 6 वर्षों की दर पर चीन के निर्यात की वृद्धि (वास्तविक कीमतों पर 7 प्रतिशत वार्षिक) भी विश्व निर्यात-जीडीपी अनुपात में 1.4 प्रतिशत बिन्दुओं का योगदान देगी। दूसरे शब्दों में भारत को विश्व की वैश्वीकरण धारण क्षमता से टकराना होगा। यदि विश्व व्यापार जीडीपी अनुपात में कमी आई तो यह टकराव और भीषण हो जाएगा। चीन का प्रगति रथ चलते रहने पर उक्त भीषणता और प्रखर होगी।

भारत की दृष्टि से वैश्वीकरण धारण क्षमता केवल वस्तुओं नहीं सेवाओं के पटल पर भी महत्वपूर्ण है। विश्व का सेवा निर्यात जीडीपी अनुपात लगभग 6.1 प्रतिशत है। यदि भारत सक्रिय सेवा निर्यात के सहारे तीव्र संवृद्धि पाता है तो विश्व के सेवा निर्यात जीडीपी अनुपात में 0.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि संभव है। यह वैश्विक निर्यात का एक बहुत बड़ा अंश होगा। दूसरे शब्दों में, भारत की सेवा निर्यात वृद्धि विश्व की सेवा क्षेत्रीय धारणीय क्षमता की कड़ी परीक्षा लेगी। इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं श्रम की गतिशीलता ही नहीं वरन् उन्नत देशों द्वारा 'बाह्य प्रापण' (बाहर से काम कराने-आउटसोर्सिंग) पर नियंत्रण प्रतिबंध का रूप धारण कर सकती हैं।

यह संभव है कि विश्व की भारतीय सेवाओं की धारण क्षमता उससे अधिक रहे जो चीन की वस्तुओं के प्रति थी। कारण यही है कि चीन का वस्तु निर्यात प्रसार कई दृष्टियों से असंतुलित था, उसके निर्यात आयातों से बहुत अधिक थे, वह उन्नत देशों को विनिर्मित वस्तुएं निर्यात कर रहा था और उनके अपने उत्पादन को कुप्रभावित कर रहा था, साथ ही वह विकासशील देशों से कच्चा माल आयात करता था। यदि उसने विकसित देशों से कुछ मंगाया तो वह सेवा क्षेत्र का उत्पादन ही था।³ परिणामस्वरूप चीन को निर्यात ने उन्नत देशों में बहुत कम निर्यात प्रेरित रोजगार के अवसरों का सृजन किया है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार हानि हुई है। जो रोजगार वृद्धि हुई वह भी उच्चस्तरीय (वित्त आदि) सेवाओं में हुई थी, जो विनिर्माण से विस्थापित श्रमिकों की पहुंच से बाहर थे।

इसके विपरीत, भारत के निर्यात की वृद्धि अधिक संतुलित हो सकती है। भारत में चालू खाते पर निरंतर घाटा चल रहा है, अतिरेक नहीं। भारत के सेवा निर्यात से भी उन्नत देशों में कुछ कर्मी विस्थापित होंगे, किन्तु उन्हें वैकल्पिक रोजगार पाना सरल होगा, वे और आधुनिक सेवाओं की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे (जैसे कि अधिक उन्नत स्तर पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि)। किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है : भारतीय स्पर्धा का प्रभाव उन्नत देशों की कौशल संपन्न श्रमशक्ति पर पड़ेगा और उसकी राजनीतिक स्तर पर आयात विरोध के आयोजन की क्षमता भी अधिक होती है।

कुल मिलाकर उन्नत देशों में वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलित करने में कठिनाइयां भारत की आर्थिक संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। आने वाले वर्षों दशक भर तो अवश्य उन पर ध्यान देना होगा।

³ पूंजीगत पदार्थों का आयात एक अपवाद रहा है।

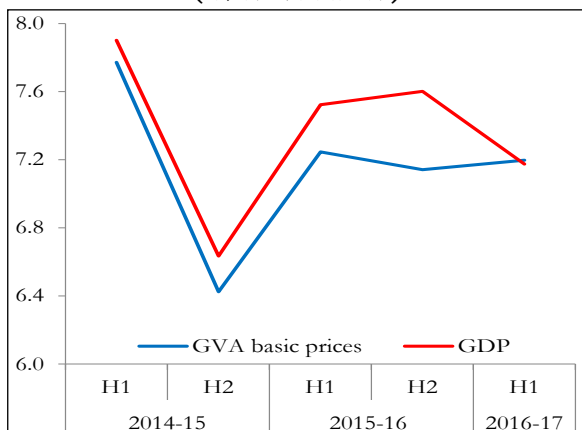
ऐसी अव्यवस्था को सृजित कर देगा कि भारत उससे अछूता नहीं रह पाएगा (देखें अनुच्छेद VI 'ख')। मुद्रा को लेकर चीन को कम से कम दो कठिन संतुलन साधने होंगे। आन्तरिक रूप से करेंसी में हास (और साख प्रसार) अल्पकाल में अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं, किन्तु उससे न केवल पुनःसंतुलन आगे की ओर खिसक जाएगा, बल्कि मध्यकालिक चुनौतियां भी और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी पलायन की प्रतिक्रिया स्वरूप करेंसी का क्षरण होने देना व्यापार में टकराव पैदा करेगा। साथ ही पूंजी नियंत्रण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को हतोत्साहित करेंगे और युवान को विश्व की सुरक्षित करेंसी के रूप में स्थापित करने की चीनी महत्वाकांक्षा पर आघात होगा। अपनी अंतर्निहित भेद्यताओं के कारण आज चीन वह देश बन गया है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में भीषण व्यावधान उत्पन्न करने की बहुत क्षमता है।

III. वर्ष 2016-17 के घटनाक्रम की समीक्षा

(क) जीडीपी और मुद्रास्फीति

1.28 पिछली समीक्षा की प्रस्तुति के बाद के 11 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने समष्टि आर्थिक स्थिरता की दिशा में अपनी उपलब्धियों का निरंतर पोषण है।

रेखाचित्र 1क : सकल मूल्यवृद्धि और जीडीपी संवृद्धि (स्थिर कीमतों पर)

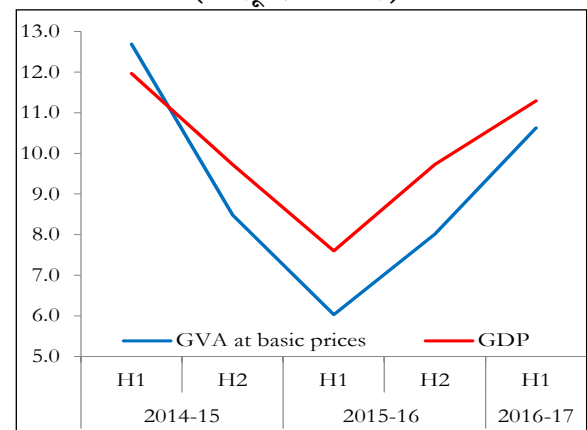


स्रोत: सीएसओ

1.29 वर्ष के पूर्वाद्ध में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि आर्थिक समीक्षा 2015-16 के पूर्वाकलन 7.0-7.5 प्रतिशत की निम्न सीमा के अधिक निकट 7.2 प्रतिशत रही। यह 2015-16 के उत्तराद्ध की दर 7.6 प्रतिशत से निश्चित रूप से कम थी (रेखाचित्र 1क)। समस्या का मुख्य स्रोत रहा अचल निवेश। इसमें काफी कमी आई, फर्मों की विषादगस्त तुलनपत्र अवस्था के उनकी निवेश व्यय योजनाओं पर गहरे प्रभाव रहे। सकारात्मक पक्ष पर सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्णय (सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि) से अर्थव्यवस्था में व्यय पक्ष में सुधार हुआ। साथ ही विकसित देशों की मांग में सुधार के कारण निर्यात में चिरप्रतीक्षित वृद्धिक्रम में भी त्वरण के चिन्ह दिखाई देने लगे। सामान्य जीडीपी सम्मानपूर्ण स्तर पर पहुँच गई और 2015-16 के पूर्वाद्ध जैसी तीखी एवं चिन्ताकारी गिरावट की प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल गई (देखें रेखाचित्र 1ख)।⁴

1.30 वर्ष 2016-17 के पूर्वाद्ध में क्षेत्रवार संवृद्धि निष्पादन की विशेषताएं ये रही : (i) औद्योगिक एवं गैर सरकारी सेवा क्षेत्रों में कुछ शिथिलता; (ii) बेहतर मानसून के सहारे कृषि संवृद्धि में सुधार; और (iii) लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा सेवाओं में अच्छी संवृद्धि (कुल मिलाकर उन्नयकारी एवं दमनकारी कारकों ने परस्पर संतुलन प्रायः स्थापित कर लिया है और इस

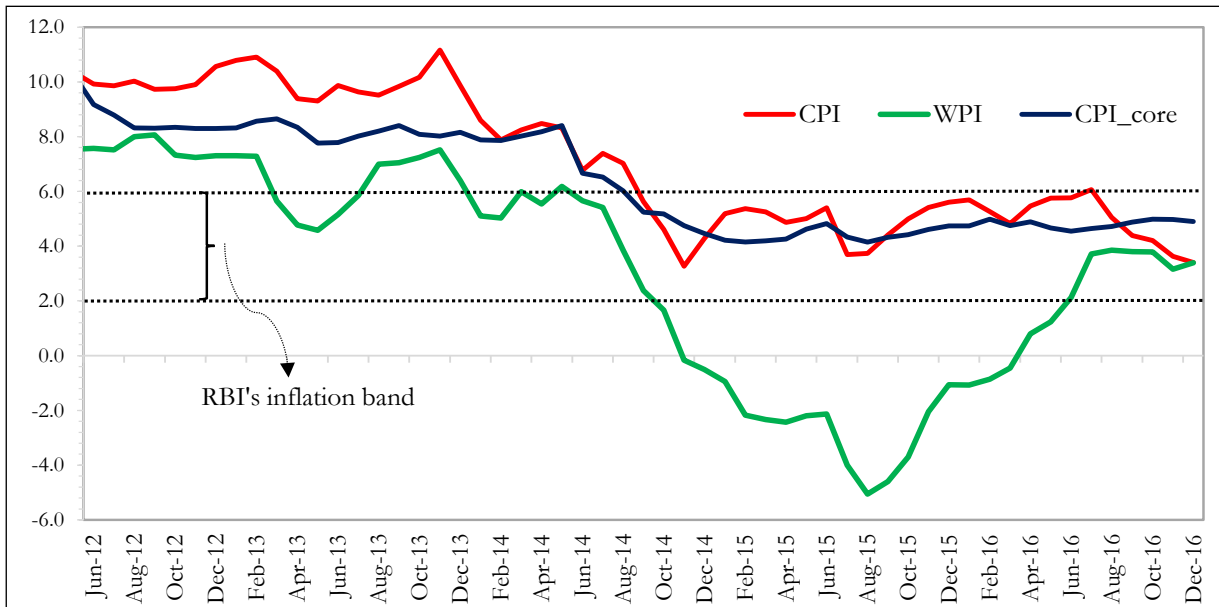
रेखाचित्र 1ख : सकल मूल्यवृद्धि और जीडीपी संवृद्धि (चालू कीमतों पर)



स्रोत: सीएसओ

⁴ सामान्यतः चालू कीमतों पर जीडीपी संवृद्धि में नीतिनिर्माताओं की विशेष रुचि नहीं होती। किन्तु जब जीडीपी 'अपस्फायक' (deflator) के आंकलन में असामान्य मापन की अनिश्चिता आ जाए तो चालू कीमतों पर संवृद्धि वास्तविक गतिविधियों के विषय में अतिरिक्त जानकारी अवश्य सुलभ करा देती है।

रेखाचित्र 2 : थोक कीमत सूचक एवं उपभोक्ता कीमत सूचक के अनुसार स्फीति



स्रोत: सीएसओ

प्रकार सकल मूल्य वृद्धि में संवृद्धि का मान 7.2 हो गया, जो 2015-16 के उत्तरार्द्ध के मान (7.1 प्रतिशत) के समान प्रायः ही था (देखें रेखाचित्र-1क))।

1.31 इस वर्ष मुद्रा स्फीति के दो विशेष लक्षण रहे हैं (रेखाचित्र-2)। उपभोक्ता कीमत सूचक CPI की नई श्रृंखला, जिसके अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2016 की अवधि में औसत स्फीति 4.9 प्रतिशत थी, में जुलाई के बाद से निरंतर गिरावट आ रही है। उसी समय यह स्पष्ट संकेत मिलना प्रारंभ हो गए थे कि खरीफ की फसल अच्छी होगी और दालों का उत्पादन विशेष रूप से प्रचुरतापूर्ण होगा। दालों की कीमत में कमी का CPI स्फीति में गिरावट में बड़ा योगदान रहा है, यह दिसंबर के अंत तक घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई है।

1.32 दूसरी विशेषता थोक कीमत सूचक WPI आधारित स्फीति मापक की दिशा का परिवर्तन है। यह अगस्त 2015 के (-) 5.1 प्रतिशत बढ़कर दिसंबर 2016 के अंत तक 3.4 प्रतिशत हो गई थी (देखें रेखाचित्र-2)। अब WPI और CPI के बीच की वह खाई, जो जीडीपी मापन में एक गंभीर समस्या का कारण बन रही थी, अब काफी संकीर्ण रह गई है (इसके विषय में 2015-16 के वर्ष मध्य आर्थिक विश्लेषण (MYEA) के बॉक्स-3 में चर्चा की गई थी)। अन्तस्थ रूप से स्फीति में अधिक स्थिरता रही है, यह इस वर्ष अभी तक 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच रही है।

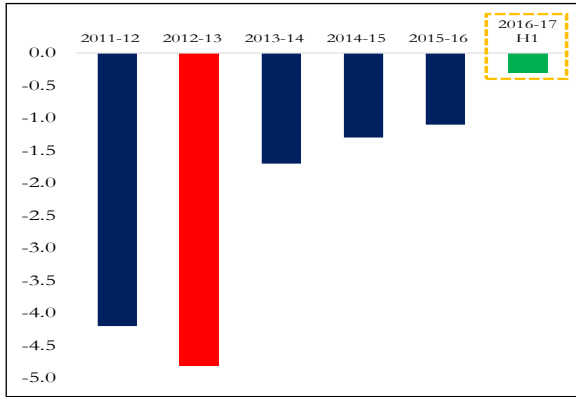
1.33 अपेक्षा है कि पूरे वर्ष भर CPI स्फीति का स्तर रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित 5 प्रतिशत से कम ही रहेगा, इसमें विमुद्रीकरण का सहायक प्रभाव भी झलक रहा है।

(ख) बाह्य क्षेत्र

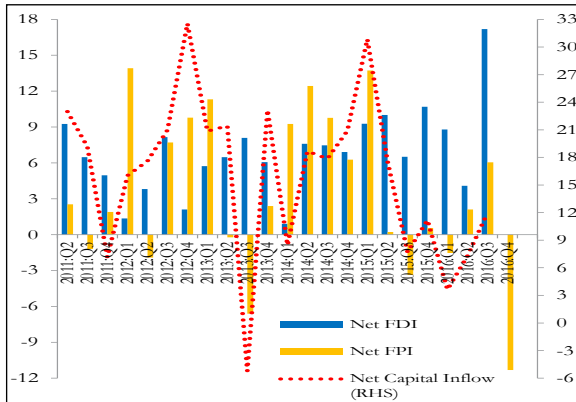
1.34 इसी प्रकार बाह्य क्षेत्र की दृष्टि से भी स्थिति सुदृढ़ दिखाई दे रही है। 2016 के अंत में विशाल आकार की गैर-नागरिक विदेशी मुद्रा जमाओं का सफलतापूर्ण भुगतान हो चुका है तथा अमेरिकी चुनाव और विमुद्रीकरण संबंधित अस्थिरता पर भी पार पाया जा चुका है। चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2017 के पूर्वार्द्ध में घटकर जीडीपी का 0.3 प्रतिशत रह गया है। जनवरी 2016 के \$350 बिलियन से बढ़कर दिसंबर 2016 में विदेशी मुद्रा भंडार \$360 बिलियन के अच्छे स्तर पर पहुँच गए हैं। यह सुरक्षित कोष की पर्याप्तता के मानक स्तर से कहीं अधिक है। वित्त वर्ष 2016 के प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्रवाह जीडीपी के 1.7 प्रतिशत थे। उनका वित्त वर्ष 2017 के पूर्वार्द्ध में 3.2 प्रतिशत हो जाने का भी भुगतान शेष की सुखद स्थिति में योगदान रहा है (देखें रेखाचित्र 3क से 3घ तक)।

1.35 अप्रैल-दिसंबर 2016 में पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में व्यापार घाटे में 23.5 प्रतिशत की कमी आई। वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में इसका मुख्य कारण आयात

रेखाचित्र 3क : चालू खाता संतुलन
(जीडीपी का प्रतिशत)



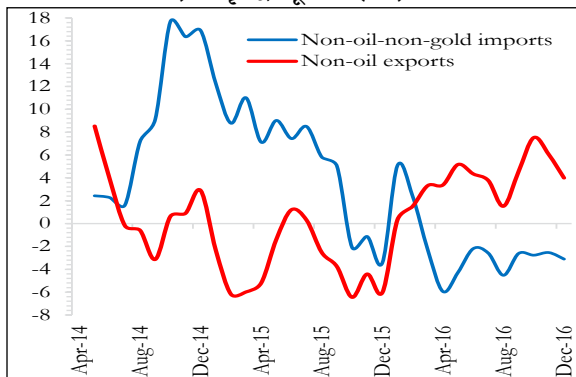
रेखाचित्र 3ग : पूंजी प्रवाहों के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियां (\$बिलियन) a*



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, इन सभी चित्रों में कैलेंडर वर्षों का प्रयोग किया गया है।

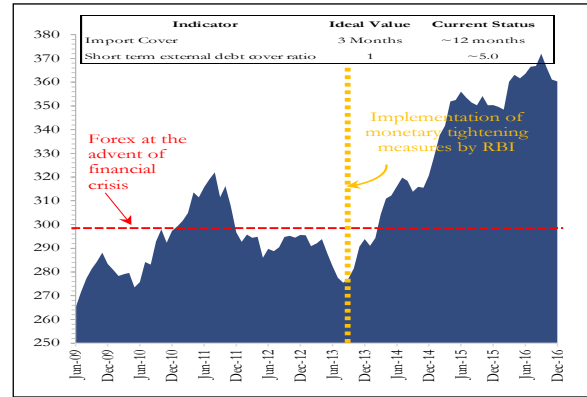
में गिरावट का निर्यात की कमी से कहीं अधिक तीखा रहना था। किन्तु, दिसंबर में निर्यात-आयात में दीर्घप्रतीक्षित सुधार आना आरंभ हो गया और इनमें 5 प्रतिशत से अधिक दर पर वृद्धि होने लगी (रेखाचित्र 4(क))। निर्यात में सुधार का संबंध विश्व अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगति से

रेखाचित्र 4क : आयात एवं निर्यात परिमाण (गैर तेल, गैर स्वर्ण) संवृद्धि सूचक (%) त्रैमासिक

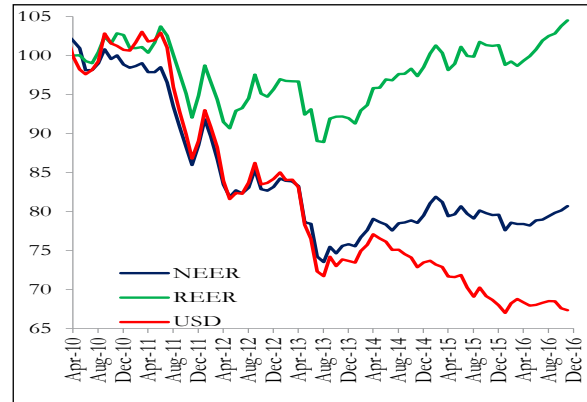


स्रोत: DGCIS तथा समीक्षा गणनाएं

रेखाचित्र 3ख : विदेशी मुद्रा भंडार
(अमेरिकी \$ बिलियन)

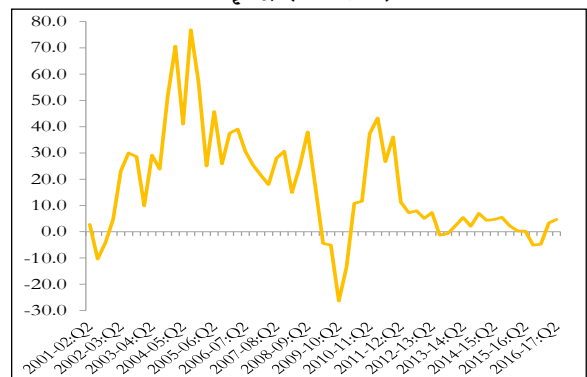


रेखाचित्र 3घ : NEER, REER और \$विनिमय दर सूचक (2010=100)



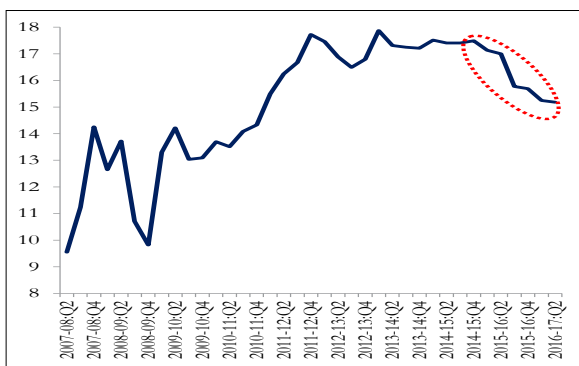
प्रतीत हो रहा है (यह अमेरिका और जर्मनी में बेहतर संवृद्धि का परिणाम है)। आयात पक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में नमी की प्रक्रिया समाप्त हो चली है और अल्प से मध्यम काल में ये कीमतें आयात के सकल खाते पर अपना प्रभाव दिखाएंगी।

रेखाचित्र 4ख : गैर साधन सेवा निर्यात संवृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: RBI और समीक्षा गणनाएं

रेखाचित्र 5 : निजी धन प्रेषण
(\$बिलियन)



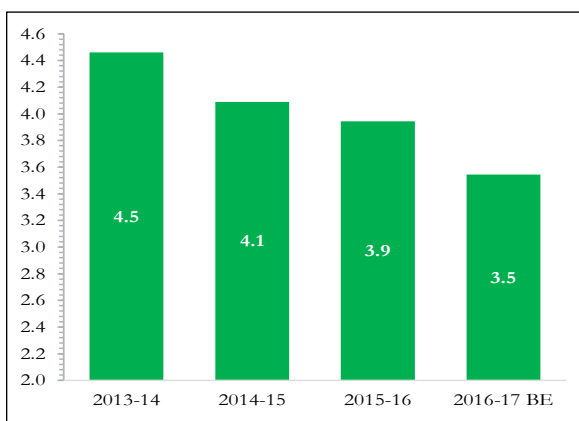
स्रोत: RBI

1.36 यही नहीं, पूर्वाद्ध में सेवा क्षेत्र का निवल अतिरेक कम होने लगा है, सॉफ्टवेयर सेवाओं की निर्यात दर धीमी पड़ रही है और वित्तीय सेवाओं का निर्यात कम हो रहा है (रेखाचित्र 4(ख))। निवल निजी धन प्रेषण में वर्ष 2015-16 की इसी अवधि की तुलना में 2016-17 के पूर्वाद्ध में \$4.5 बिलियन की कमी आई है। इसमें कुछ प्रभाव तेल कीमतों की कमी के कारण खाड़ी क्षेत्र से आवकों में कमी का भी रहा है (रेखाचित्र-5)।

(ग) राजकोषीय

1.37 राजकोषीय क्षेत्र में कोई अप्रत्याशित रुझान नहीं दिखाई दिया है और सरकार की इस वर्ष जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के स्तर पर राजकोषीय घाटा सीमित रखने की प्रतिबद्धता सफल होती दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष अपनाए गए अधिक राजस्व सृजक कदमों

रेखाचित्र 6क : केंद्र का राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)

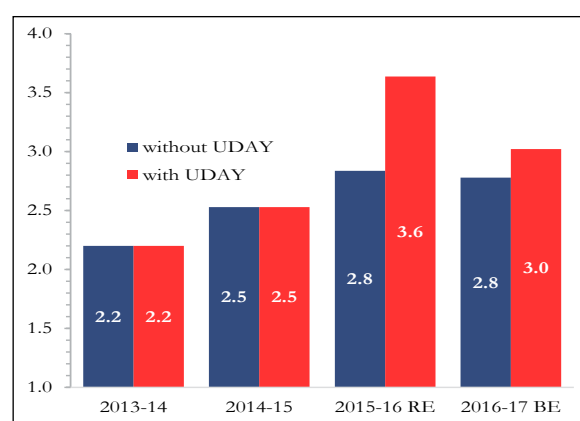


स्रोत: केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज

से उत्पादन शुल्क और सेवाकर संग्रह में सुधार आया है। सबसे प्रमुख बात तो उत्पादन शुल्क संग्रह में आया बड़ा उछाल है, यह बजट अनुमान से भी अधिक है। इसका कारण तेल उत्पादों के उपभोग में भारी उछाल है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2016-17 में इस उपभोग में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर संग्रह भी मजबूती भरा रहा है। इसका आंशिक कारण विमुद्रीकरण से तेल उपभोग को मुक्त रखना भी है। जिसके परिणाम स्वरूप तेल पदार्थों पर उत्पादन शुल्क पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अधिक व्यापक स्तर पर कर संग्रह का अपेक्षा से उच्चतर बने रहने का एक कारण पुराने नोटों की कर भुगतान के लिए वैधता बनी रहना भी था। टेलीफोन स्पेक्ट्रम की बिक्री और विनिवेश से प्राप्त कम रहना (उनकी अति आशावादी पूर्वापेक्षा की तुलना में) तथा सार्वजनिक उद्यमों में चल रही दबाव की स्थिति के कारण लाभांश में कमी के परिणाम स्वरूप गैर कर राजस्व संकलन में कुछ बाधाएं आई हैं।

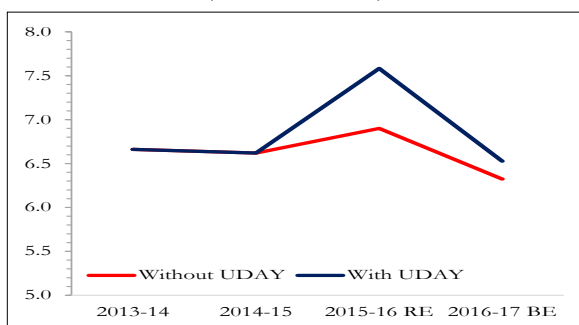
1.38 राज्य सरकारों के वित्त में भी कुछ तनावपूर्ण स्थिति बनी है (रेखाचित्र 6(ख))। पिछले कुछ वर्षों से राज्यों के समेकित घाटे में निरंतर वृद्धि चल रही है। यह 2014-15 के जीडीपी के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 3.6 प्रतिशत हो गया था। इसका आंशिक दायित्व 'उदय (UDAY)' योजना पर भी है। बजट अनुमानों से इस वर्ष अवस्था में सुधार होने के संकेत

रेखाचित्र 6ख : राज्यों का राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)



स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

रेखाचित्र 6ग : सामान्य सरकार का राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)



स्रोत: बजट दस्तावेज

मिल रहे हैं। किन्तु बाजारों के कुछ फिसल जाने की आशंकाएं भी हैं। यह संवृद्धि में कुछ शिथिलता की अपेक्षा, स्टैप शुल्क संग्रह में कमी तथा राज्यों के अपने वेतन आयोगों की सिफारिशों लागू होने का मिलाजुला परिणाम होगा। इन्हीं के फलस्वरूप अक्टूबर 2016 के 45 बिन्दुओं की अपेक्षा जनवरी 2017 में राज्य सरकारों के बांड अन्य सरकारी निक्षेपों की तुलना में 75 आधारिक बिन्दुओं का अन्तराल दिखाने लगे हैं।

1.39 सामान्य प्रशासन स्तर पर उदय योजना के साथ भी और उसके बिना भी, राजकोषीय घाटे की स्थिति में सुधार ही दिखाई दिया है (देखें रेखाचित्र 6ग)।

IV. वर्ष 2016-17 की संभावनाएं

1.40 इस वर्ष की संभावनाओं/अपेक्षाओं का मूल्यांकन 8 नवंबर को उच्चमान के करैंसी नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाना चाहिए। किन्तु उससे पूर्व अल्पकाल में विमुद्रीकरण के संक्षोभ का विश्लेषण समझ लेना आवश्यक है (दीर्घकालिक लाभों की व्याख्या अध्याय-3 की जाएगी)।

1.41 विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था को तीन अलग-अलग विधियों से प्रभावित करता है। संभवतः ये हैं;

- यह सकल मांग संक्षोभ का कारण बनता है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है और निजी धन संपन्नता (विशेषकर अघोषित संपदा वालों की) में कमी आती है;
- जिन क्षेत्रों में नकद का ही प्रयोग होता रहा हो वहां से आपूर्ति में बड़ी गिरावट का संक्षोभ (उदाहरण

: कृषि उत्पादन पर दुष्प्रभाव की आशंका, क्योंकि मजदूरी प्रायः नकद दी जाती है); और

- अनिश्चितता का संक्षोभ - अनेक आर्थिक कर्ता नकद प्रवाह के स्तर पर प्रभाव और उसकी अवधि को लेकर आशंकित हो जाते हैं। नीति विषयक असमंजस का प्रभाव भी रहता है (संभवतः उपभोक्ता कुछ ऐच्छिक उपभोग स्थगित कर देते हैं तो उत्पादक भी निवेश व्यय घटाने को विवश हो जाते हैं)।

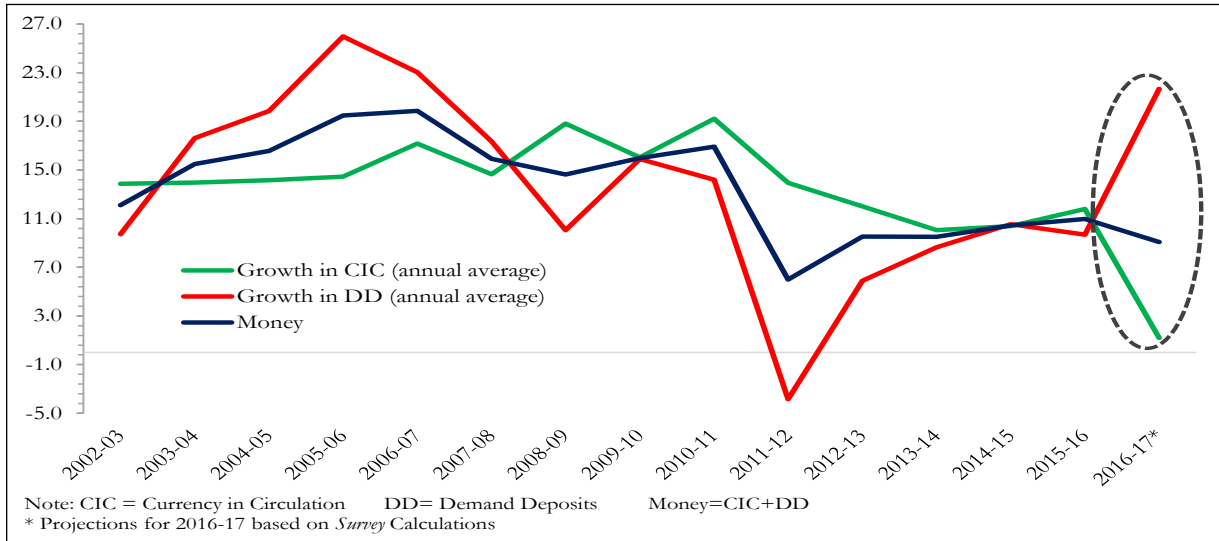
(क) नकदी एवं मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज की दरों पर प्रभाव

1.42 विमुद्रीकरण के मौद्रिक प्रभाव बहुत ही असामान्य होते हैं। इससे मुद्रा के एक स्वरूप, नकदी, की आपूर्ति में भारी कमी आई है। किन्तु साथ ही मांग जमा रूपी स्वरूप में बड़ी वृद्धि भी हुई है। कारण यही है कि विमुद्रीकृत नोटों को बैंक खातों में जमा कराया जा सकता था। रेखाचित्र 7 में लाल और हरी रेखाओं का बड़ा अंतर इसी प्रभाव को दर्शा रहा है। वित्त वर्ष 2017 के तीसरे चतुर्थांश में विमुद्रीकरण किया गया था और तुरंत ही नकदी में 9.4 प्रतिशत की कमी तथा मांग जमाओं में 43 प्रतिशत का उछाल आया। दोनों के योग में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़े क्रमशः 12.5, 10.5 और 11.7 प्रतिशत की वृद्धि के ही थे।

1.43 यदि विमुद्रीकरण के असामान्य प्रभावों के 'कीमत' पक्ष पर ध्यान दें तो नकदी की कीमत में भारी उछाल आया था (यह मुख्यतः नकद निकालने पर रूकावटों और निकासी हेतु लगी कतारों के आधार पर ही लगाया गया अनुमान है)। दूसरी ओर 9 नवंबर के बाद से उधार पर ब्याज की दर में 90 आधारिक बिन्दुओं की कमी (यह नकद कोष की सीमांत लागत पर आधारित होती है); जमाओं पर ब्याज दर में 25 बिन्दुओं की कमी तथा सरकारी निक्षेपों एवं अन्य पर 32 बिन्दुओं की कमी को हमने रेखाचित्र 8 में दिखाया है।

1.44 विमुद्रीकरण के अन्य आयाम का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सभी परिमाण एवं कीमत प्रभाव पुनः मुद्रा की दर और नीतिगत रूकावटों को हटाने के अनुसार स्वयं ही समंजित हों जाएंगे। ऐसा होते ही उपभोक्ता अपने बैंक खाते खाली कर एक बार फिर से नकदी का भंडार जमा

रेखाचित्र 7. नकद और मांग जमा वृद्धि (%)

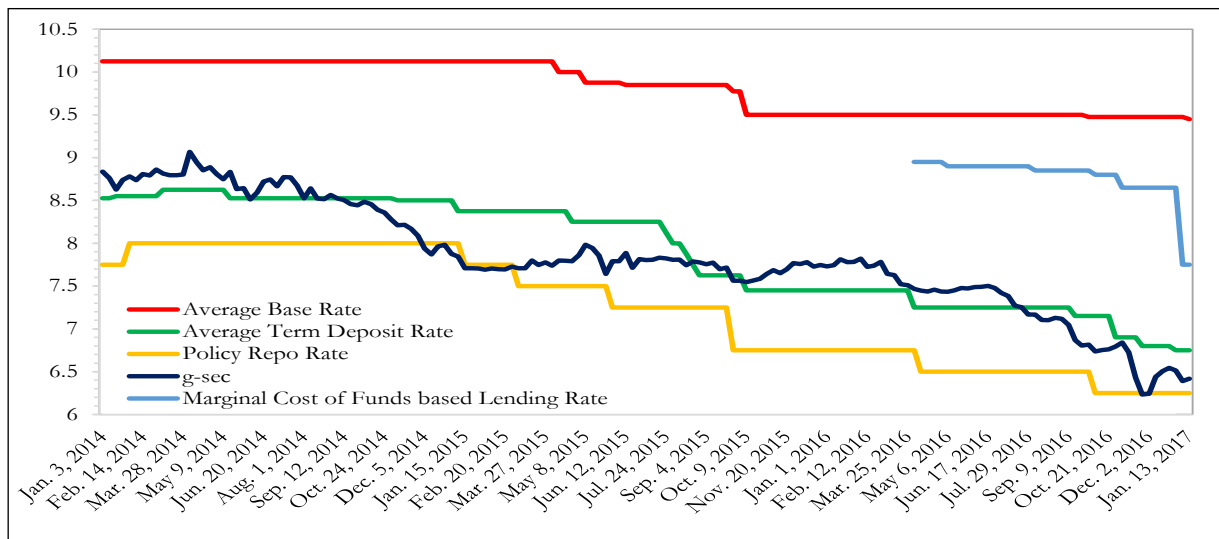


नोट : CIC=परिचलन में करेंसी; DD=मांग जमाएं; Money = CIC + DD

*वर्ष 2016-17 के पूर्वकालन समीक्षा की गणनाओं पर आधारित हैं।

स्रोत : RBI और समीक्षा की गणनाएं

रेखाचित्र 8 : रैपो दर, आधार दर और सावधि जमा दर में परिवर्तन



स्रोत: आरबीआई

कर लेंगे। हां, यह संभव ही नहीं संभावित भी है कि यह स्वयंस्मंजन संपूर्ण नहीं होगा, नई संतुलन अवस्था में सकल नकद धारिता (बैंक जमाओं और जीडीपी के अंश के रूप में) पहले से कम ही रहेगी।

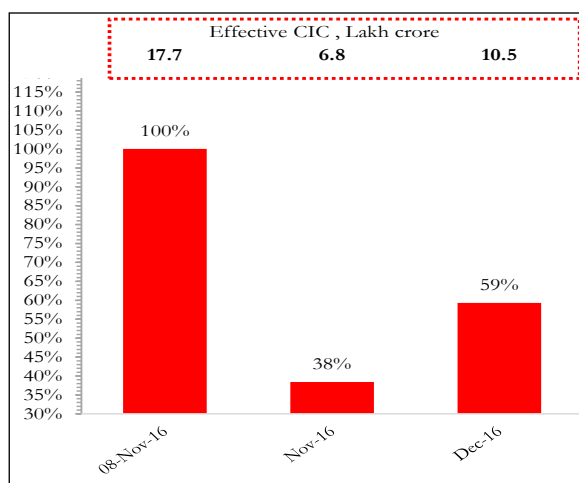
1.45 सभी मांग, आपूर्ति और अनिश्चितता प्रभावों का परिमाण निर्धारण कर पाना न केवल कठिन है, बल्कि अभी ऐसा करना एक जल्दबाजी भी होगी। रेखाचित्र 9(क)

और 9(ख) में तरलता नकदी पर प्रभावों का परिमाण निर्धारण करने के प्रयास किए गए हैं। परिचलन में नकदी के शीर्ष परिमाण और प्रभावी परिचलन के हमारे अनुमान परम संख्याओं तथा लेनदेन की मांग के अंश के रूप में दिखाए गए हैं।⁵

1.46 इन रेखाचित्रों से तीन मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं। तरलता का अभाव शीर्ष परिमाण के आंकड़ों से

⁵ शीर्ष परिमाण सभी विमुद्रीकरण नोट घटाकर एवं नए नोट जोड़कर आंकलित किया गया है। 'समीक्षा' के अनुमानों में अन्य कारकों का भी आंकलन किया गया है। 'समीक्षा' के अनुमानों में अन्य कारकों का भी आंकलन किया गया है- देखें अध्याय-3

रेखाचित्र 9क : प्रभावी करेंसी परिचलन
(बाजार की धारणा)



स्रोत : समीक्षा की गणनाएं

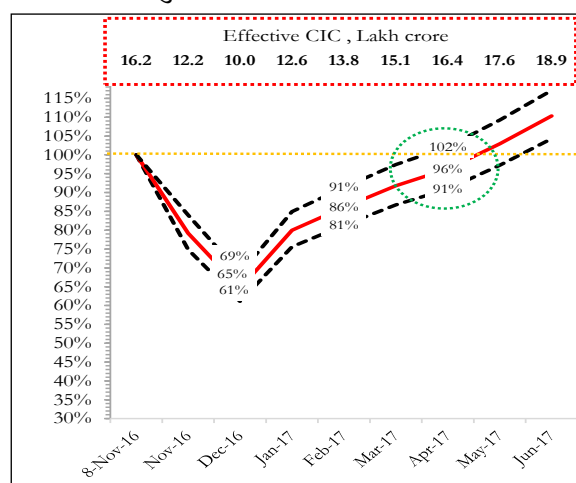
कहीं कम रहा (परिचलन में प्रभावी नकदी द्वारा मापित अभाव की यहां बात हो रही है)। शीर्ष परिमाण से तो करेंसी में 8 नवंबर से मासांत तक 62 प्रतिशत कमी की जानकारी मिल रही है। यह दिसंबर अंत तक 41 प्रतिशत रह गई थी। हमारे अभाव के अनुमान क्रमशः 25 तथा 35 प्रतिशत हैं। दूसरे शब्दों में नकदी का वास्तविक अभाव सामान्य रूप से समझे जा रहे स्तर की तुलना में बहुत कम गंभीर था।

1.47 मनोवैज्ञानिक संक्षोभ के विपरीत इस विमुद्रीकरण के वास्तविक संक्षोभ का चरम बिन्दु तो दिसंबर मास में आया था, नवंबर में नहीं। विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद कुछ सप्ताह तक प्रभावी करेंसी आपूर्ति पूर्ववत बनी रही, क्योंकि वे पुराने नोट भी प्रभावी एवं विधिक रूप से (कुछ कार्यों हेतु) स्वीकार्य बने रहे। किन्तु दिसंबर में वे सब बैंकों में जमा हो गए तथा उनके स्थान पर मिले रूपए 2000/- वाले नोटों की तरलता उतनी अधिक नहीं थी।

1.48 विभिन्न परिमाण यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अब अन्तर तेजी से मिटता जा रहा है। दिसंबर 2016 के अंत में प्रभावी करेंसी अनुमानित मांग के 65 प्रतिशत के लगभग थी और फरवरी अंत तक यह अनुपात 86 प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा है।

1.49 इन आधारिक तथ्यों का ध्यान रखते हुए हम विमुद्रीकरण के अभी तक के समष्टि आर्थिक प्रभावों की समीक्षा की ओर चल रहे हैं।

रेखाचित्र 9ख : अनुमानित लेनदेन की मांग
के अनुपात में प्रभावी करेंसी परिचलन

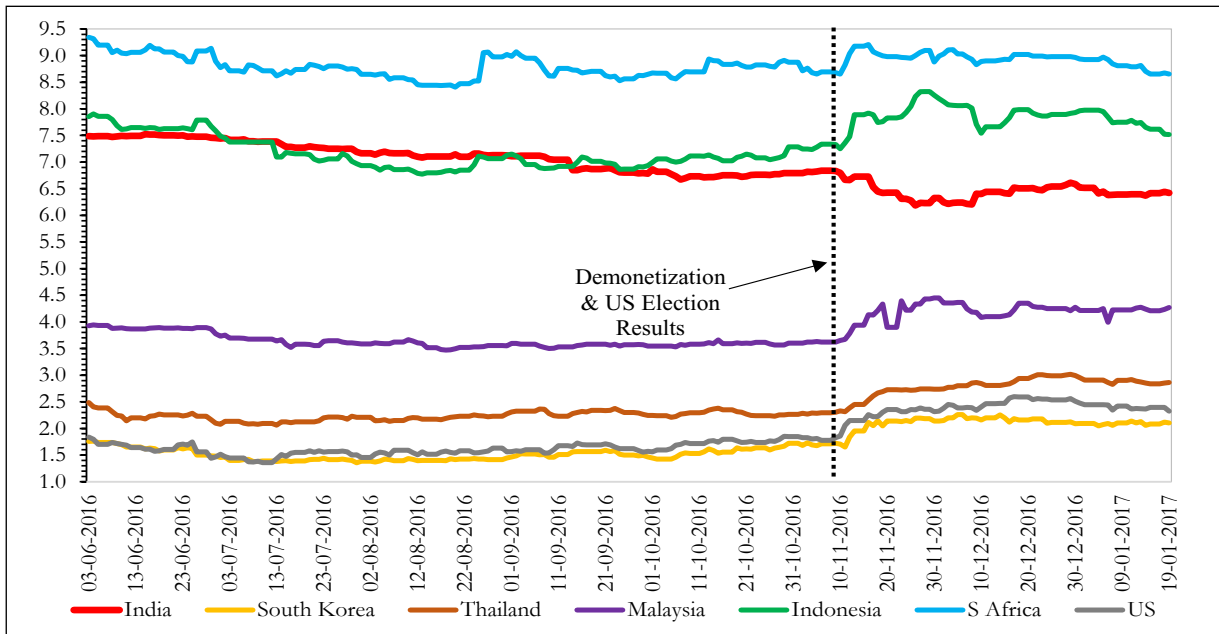


1.50 रेखाचित्र 10-12 में विमुद्रीकरण के बाद से ब्याज की दरें, विनियम दर और पूंजी (स्टॉक) मार्केट प्रभाव अंकित किए गए हैं। हमारी विमुद्रीकरण की घोषणा के साथ-साथ अमेरिका में आर्थिक पटल पर परिवर्तनों की संभावनाओं से परिपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम भी घोषित हुए हैं। अतः विमुद्रीकरण के प्रभावों को पृथक् रखते हुए (यथासंभव) हम तुलनीय उदीप्यमान बाजार व्यवस्था वाले देशों की तुलना में भारत पर संभावित प्रभावों की समीक्षा करेंगे।

1.51 सबसे नाटकीय प्रभाव तो ब्याज दरों से संबंधित है (रेखाचित्र 10)। प्रायः सभी बड़े देशों में बांडों पर प्रतिप्राप्ति में 8 नवंबर के बाद से उछाल आया है, जनवरी 19 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में तो यह उछाल 58 आधारिक बिन्दुओं तक पहुँच चुका था। किन्तु भारत में यह परिवर्तन विपरीत दिशा में 32 बिन्दु रहा। अर्थात् तुलनात्मक दृष्टि से 90 बिन्दुओं का बदलाव आया। इसी प्रकार भारत के शेयर बाजार में 0.93 प्रतिशत की गिरावट रही (रेखाचित्र 11)।

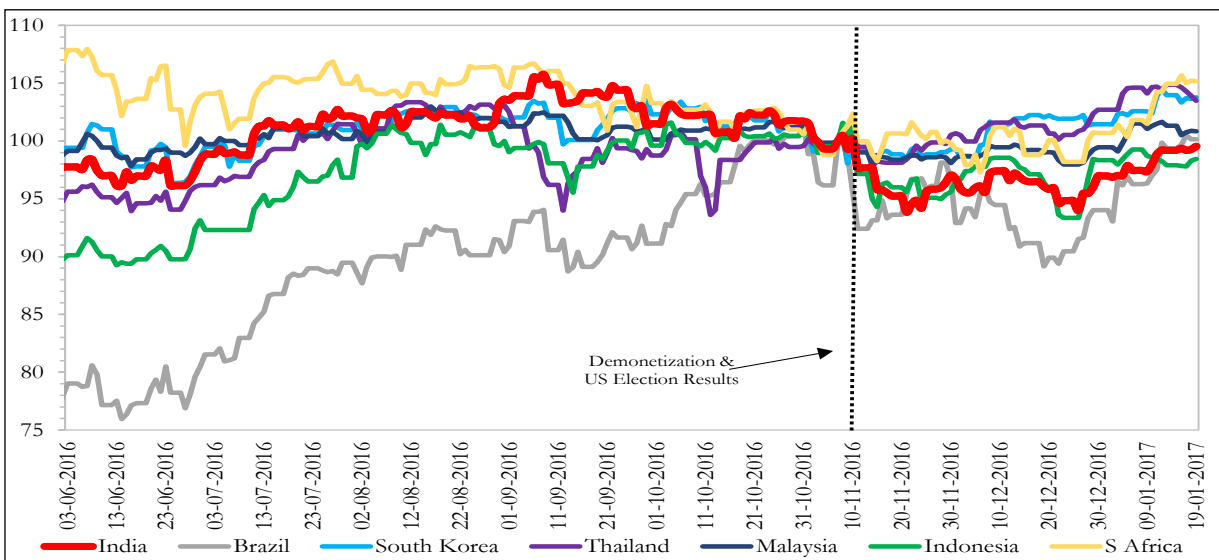
1.52 ब्याज दरों तथा संभावनाओं में गिरावट के कारण पत्रक निवेशकर्ता विदेशियों में भगदड़ मची और नवंबर-दिसंबर में \$9.8 बिलियन की राशियां वापस चली गई, इसका 60 प्रतिशत तो ऋण के रूप में आई राशियां ही थीं (3ग)। फिर भी विचित्र सा लगता है कि विनियम दर पर प्रभाव बहुत सामान्य सा रहा (रेखाचित्र 12)। संभवतः इसका एक बड़ा कारण भारतीय रिजर्व

रेखाचित्र 10 : सरकारी बाँडों पर प्रति प्राप्ति (%)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

रेखाचित्र 11 : शेयर कीमतें (नवंबर 7 = 100)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

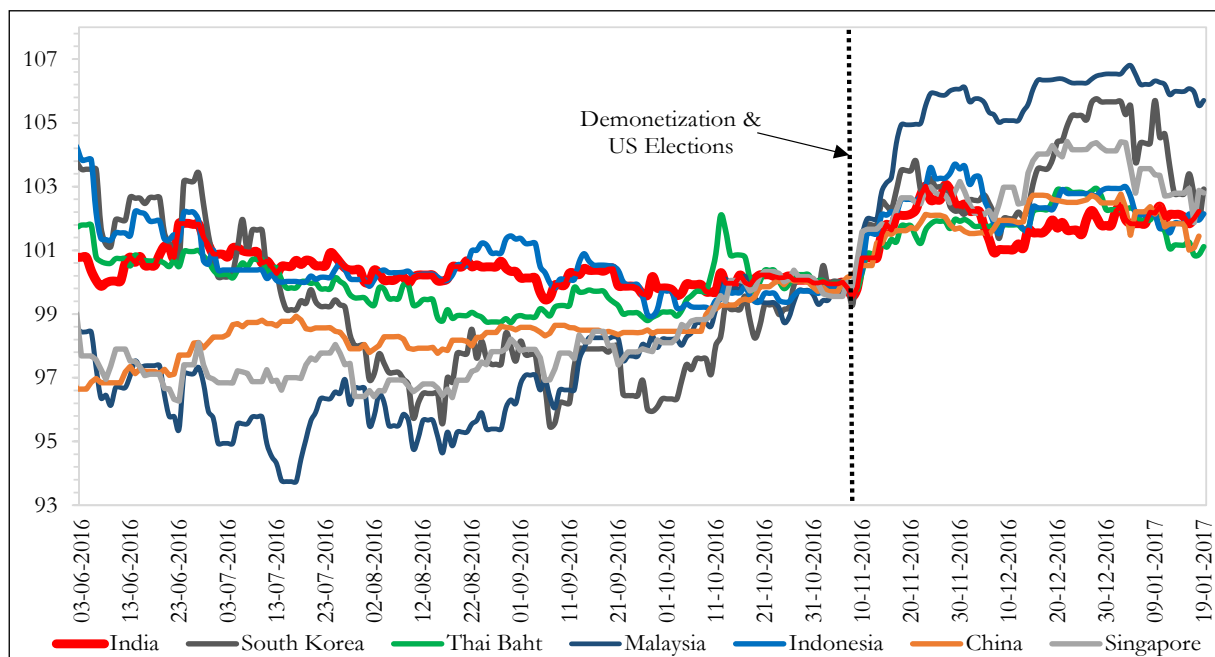
बैंक द्वारा रूपए की स्थिरता बनाए रखने हेतु अपनाए गए कदम ही हैं।

(ख) जीडीपी पर प्रभाव

1.53 विमुद्रीकरण के प्रभावों पर घटनावृत्तों और सर्वेक्षण आधारित आंकड़ों की भरमार है। किन्तु हमारी रुचि तो समष्टि स्तरीय मूल्यांकन में है और इसीलिए हम पाँच बृहत्तर सूचकों पर ध्यान दे रहे हैं।

- कृषि (रबी) की फसल की बुआई;
- उत्पादन एवं विक्रय के व्यापक मापक के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व;
- ऐच्छिक उपभोक्ता के सूचक : दुपहिया वाहनों पर व्यय, जो ग्रामीण एवं अपेक्षाकृत कम धनिक वर्ग की मांग को दर्शाता है;
- वास्तविक साख संवृद्धि; और

रेखाचित्र 12 : विनिमय दर में 7 नवंबर के बाद से परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग

- भवन संपदा कीमतें।

1.54 प्रारंभिक आशंकाओं के विपरीत 15 जनवरी 2017 तक दो मुख्य रबी की फसलों, गेहूँ और चना (दालों) की कुल बुआई पिछले वर्ष से 7.1 तथा 10.7 प्रतिशत अधिक भू-भाग में हो चुकी थी (रेखाचित्र 13)। मौसम और मिट्टी में नमी की उचित मात्रा उत्पादन में वृद्धि होने के पूर्व संकेत हैं। इन सहायक कारकों का लाभ का लाभ उठा पाना किसानों की उर्वरक, साख और श्रम जुटा पाने की क्षमता पर निर्भर रहेगा।

1.55 अन्य उच्च प्रायिकता सूचकों का परिदृश्य मिला जुला है (देखें रेखाचित्र 14-17)। यात्री कारों की बिक्री और उत्पादन शुल्क संग्रह पर विमुद्रीकरण का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता; बड़े शहरों में भवन संपदा बाजार में मंदी तथा दुपहिया वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट आई है; साख में विमुद्रीकरण से पहले ही चल रही नरमी और गहरी हो गई⁶ यदि 2016-17 में अपनाई गई अन्य नीतियों के प्रभाव का समंजन कर दें तो अप्रत्यक्ष कर संकलन शीर्षकित संख्याओं की अपेक्षा कम प्रभावशाली रह जाता है। इनकी संवृद्धि दर

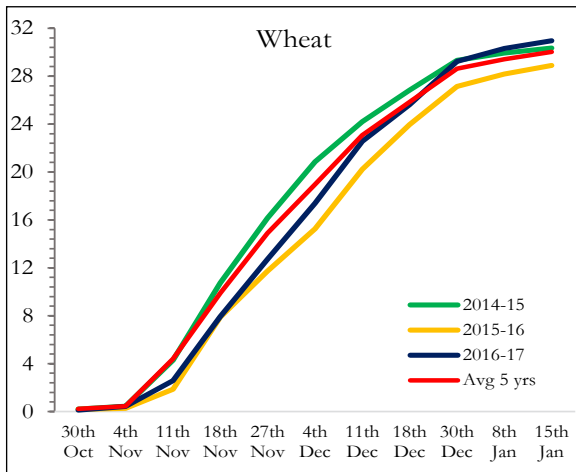
धीमी पड़ रही थी, किन्तु 8 नवंबर के बाद कोई विशेष धीमापन नहीं आया। उपलब्ध साक्ष्य संकेत दे रहे हैं कि वास्तविक जीडीपी और आर्थिक गतिविधि पर कुछ अस्थायी विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ा है। किन्तु प्रश्न यह है कि वह प्रभाव कितना बड़ा है?

1.56 विमुद्रीकरण के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए हम एक विपरीत तथ्य से प्रारंभ कर रहे हैं। विमुद्रीकरण नहीं होने पर प्रचलित कीमतों पर संवृद्धि का हमारा श्रेष्ठतम अनुमान 11 1/4 प्रतिशत था (यह पिछले वर्ष की समीक्षा से कुछ अधिक था, क्योंकि थोक कीमत सूचक में तेजी से वृद्धि होने लगी थी)। किन्तु यह केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के प्रारंभिक पूर्वानुमान 11.9 प्रतिशत से कुछ कम था। हां, वास्तविक रूप में दोनों ही पूर्वकलन 7 प्रतिशत दर पर सहमत थे।

1.57 विमुद्रीकरण के बाद संवृद्धि के आंकलन के लिए हम मुद्रा और जीडीपी का संबंध निरूपण करने के एक सरल प्रतिमान का प्रयोग कर रहे हैं। फिर, अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रयोग और डिजिटल भुगतान की ओर अग्रसर होने के परिणाम का अनुमान लगाने वाली

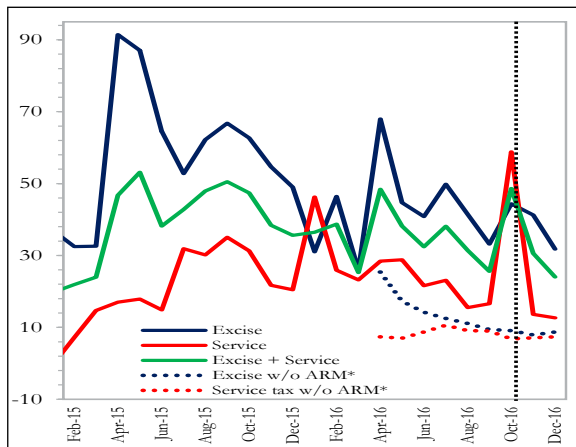
⁶ साख वृद्धि में नरमी की कुछ भरपाई तो बाँड, बाहरी व्यापारिक उधार (EcBs) तथा व्यापारिक पत्राकों के माध्यम से हो गई लगती है।

रेखाचित्र 13 : गेहूँ और चने की बुआई (मिलि. हैक्टेयरों में)



स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

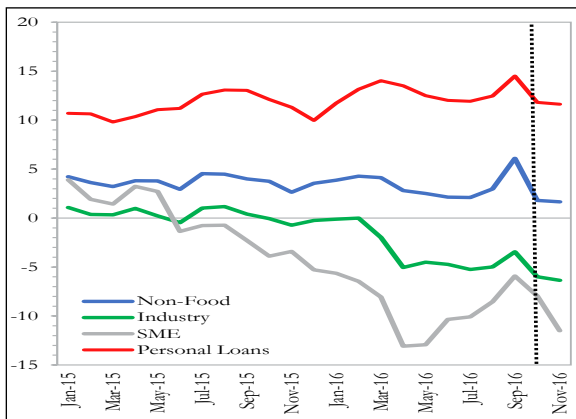
रेखाचित्र 14 : अप्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि (मौसमी समंजन के बाद, प्रतिशत)



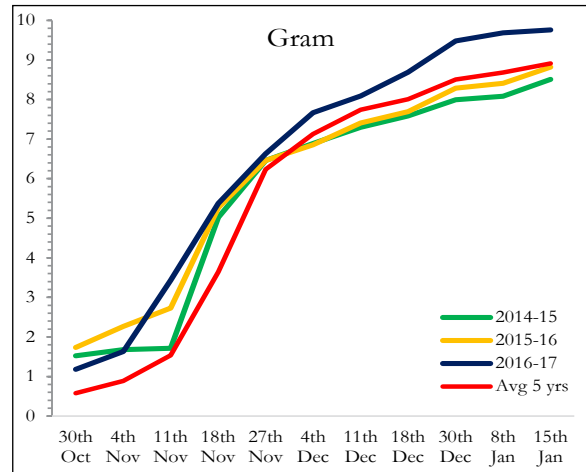
स्रोत: राजस्व विभाग और समीक्षा गणना

* संचयी वृद्धि

रेखाचित्र 16 : वास्तविक साख वृद्धि (प्रतिशत, मौसमी समंजन के बाद)

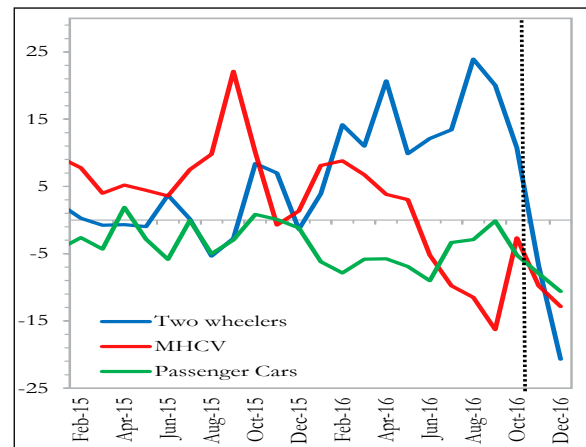


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और समीक्षा गणना

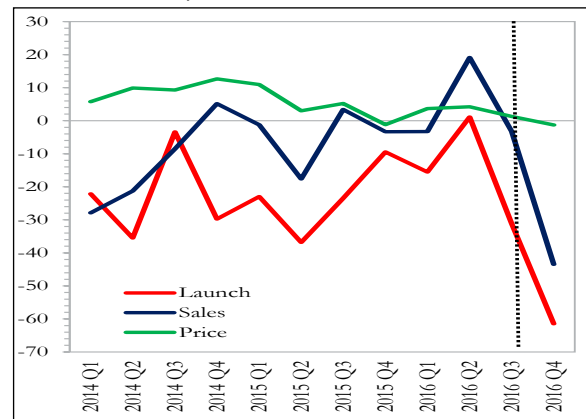


स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

रेखाचित्र 15 : वाहन विक्रय वृद्धि, प्रतिशत, मौसमी समंजन के बाद



स्रोत: एसआईएम

रेखाचित्र 17 : भवन-संपदा कीमतें (%, मौसमी समंजन के बाद)⁷

स्रोत: नाइट फ्रैंक डाटा और और समीक्षा गणना

⁷ भवन संपदाओं की कीमतों के त्रैमासिक आंकड़ों को कैलेंडर वर्षानुसार अंकित किया गया है।

मान्यताओं के आधार पर हम वित्तवर्ष 2017 में प्रचलित कीमतों पर तथा वास्तविक जीडीपी की संवृद्धि पर प्रभाव का आंकलन करेंगे। अभी तक चल रही अनिश्चितता के कारण ही हम प्रचलित कीमतों पर जीडीपी संवृद्धि दर में 1/4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक तथा वास्तविक जीडीपी में 1/4 प्रतिशत से 1/2 प्रतिशत तक कमी आने का पूर्वकलन कर रहे हैं। ध्यान रहे कि संवृद्धि का आधारिक मान तो 7 प्रतिशत है। मध्यम अवधि में ही जीएसटी लागू करने, विमुद्रीकरण के अनुषांगिक कदम उठाने और अन्य संरचनात्मक सुधार करने से अर्थव्यवस्था अपने वास्तविक जीडीपी में 8 से 10 प्रतिशत संवृद्धि कर पाने के सामर्थ्य को फलीभूत कर पाएगी। अच्छे एवं स्वयं संपूरक कारणों से 2016-17 के पूर्वानुमानों की तुलना अन्य वर्षों के अनुमानों से ही की जाएगी। इन तुलनाओं की सटीक एवं कुछ कम सटीक विधियों का वर्णन बॉक्स-3 में किया जा रहा है।

1.58 वित्त वर्ष 2016-17 के उत्तरार्द्ध में दर्ज होने वाली जीडीपी संवृद्धि विमुद्रीकरण के प्रभावों का न्यूनांकन करेगी, कारण यही है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में इस घटना से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों, अनौपचारिक और

नकद आधारित क्षेत्र के लिए भी औपचारिक क्षेत्र प्रदर्शन के आधार पर एक गढ़ा हुआ अनुमान जोड़ लिया जाता है। उदाहरण के लिए औपचारिक विनिर्माण का काम औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक द्वारा चलाया जाता है। यह मुख्यतः बड़े उद्योगों के निष्पादन पर आधारित है। अतः उत्पादन एवं आपूर्ति या आर्थिक गतिविधि के स्तर पर प्रभाव का न्यूनांकन होगा। हां, अनौपचारिक क्षेत्र की निम्न आय के औपचारिक क्षेत्र के उत्पादन की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव किसी सीमा तक आंकलन का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण : दुपहिया वाहनों की मांग - बॉक्स-3।

1.59 ये अनुमान लगभग पूरी तरह से विमुद्रीकरण के तरलता प्रभाव पर आधारित हैं- इनमें संपदा, सकल आपूर्ति और अनिश्चितता प्रभावों को समाहित नहीं किया है (वैसे इन सभी प्रभावों का गुणात्मक स्वरूप में आंकलन भी कठिन ही रहता है)। संभव है अनिश्चितता के कारण कुछ उपभोक्ताओं ने अपनी मांग तथा उत्पादकों ने अपने निवेश निर्णय तीसरे चतुर्थांश में स्थगित किए हैं। किन्तु जैसे-जैसे अर्थतंत्र का पुनःमुद्रीकरण होगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, अनिश्चितता समाप्त होगी तो वित्त वर्ष के अंत तक ये व्यय भी पुनः पूर्ववत् स्तरों को छूने लगेंगे। यही

बॉक्स 3 : जीडीपी विमुद्रीकरण प्रभावों में गलत व्याख्याओं की कुछ आशंकाएं

सीएसओ तथा समीक्षा के जीडीपी संवृद्धि अनुमानों, विशेषकर विमुद्रीकरण के प्रभावों में कई प्रकार की गलत व्याख्याओं की संभावना हो सकती है, उनको पहले से ही भांप कर उनका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए कुछ टिप्पणिकारों को इस वर्ष की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के अनुमान की पिछले वर्ष की दर 7.6 प्रतिशत से तुलना करने की उत्सुकता होगी। किन्तु यह अनुपयुक्त होगा, क्योंकि विमुद्रीकरण के अतिरिक्त अन्य अनेक कारकों का इस वर्ष के निष्पादन पर प्रभाव रहा है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट बंद हो गई है; उसके कारण अर्थव्यवस्था को मिलने वाले उत्कर्ष संप्रेरण अब शिथिल पड़ गए हैं। अतः विमुद्रीकरण के बिना भी संवृद्धि दर में कुछ अंतर तो अवश्य आना ही था।

अतः तुलना का उचित आधार वास्तविक संवृद्धि की वह दर होगी जो विमुद्रीकरण नहीं होने की स्थिति में प्राप्त हो सकती। यहां एक विपरीत तथ्य सीएसओ का वास्तविक जीडीपी का अग्रिम अनुमान 7.1 प्रतिशत होगा, वह समीक्षा के विपरीत तथ्य के निकट ही है।

एक कहीं बेहतर आधार वास्तविक नहीं, बल्कि प्रचलित कीमत पर जीडीपी की संवृद्धि हो सकता है। आखिर विमुद्रीकरण वस्तुतः एक मौद्रिक मांग संक्षोभ ही है और इसके प्रभावों में भी मौद्रिक परिमाण आंकड़ों ही दिखाई देंगे। यही नहीं, जैसा कि वर्ष मध्य आर्थिक विश्लेषण (2015) में ध्यानाकर्षित किया गया था, CPI और WPI स्फीति में एक बड़ी खाई जीडीपी अपस्फायक का आंकलन करने में कठिनाइयां पैदा कर रही है (उसी अपस्फायक का प्रयोग मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है)। इस वर्ष, दिसंबर 2016 की जानकारी तो उस खाई का विस्तार शून्य रह जाने का संकेत दे रही है, फिर भी उस खाई के स्थायी रूप से भर जाने तक विमुद्रीकरण के प्रभावों का सही अभिज्ञान करने के लिए मौद्रिक या प्रचलित कीमतों पर लगाए गए अनुमान ही अधिक उपयुक्त होंगे। अतः विमुद्रीकरण के प्रभाव का सही मापन करने में प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में पाई गई संवृद्धि की तुलना या समीक्षा के इस विषयक पूर्वानुमान की विमुद्रीकरण मुक्तावस्था में जीडीपी संवृद्धि के मौद्रिक मान से तुलना का प्रयोग ही सबसे उचित होगा। सीएसओ के अनुसार यह 11.9 प्रतिशत होना था जबकि समीक्षा का अनुमान 11.25 प्रतिशत के निकट था।

अन्ततः, कुछ टीकाकारों को समीक्षा के वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के अनुमानों की विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसे संस्थानों द्वारा तैयार किए गए अनुमानों से तुलना करने की लालसा भी होगी। किन्तु उन संस्थानों का 2016-17 का विमुद्रीकरण पर आधारिक अनुमान सीएसओ के अग्रिम अनुमान और समीक्षा के अनुमान से कहीं अधिक था। अतः पूर्वानुमान का स्तर नहीं बल्कि इसमें आए परिवर्तन ही तुलना के उचित आधार होंगे।

स्थिति प्रारंभिक संपदा प्रभाव को लेकर होगी, शुरु में नकदी बैंकों में जमा करनी पड़ी, जहां से उसे निकालना कठिन था, पर निकासी पर प्रतिबंध शिथिल होने पर यह प्रभाव भी विलुप्त हो जाएगा। वस्तुतः यदि इस संपदा का कुछ अन्तरण उनको हो गया है जिनकी व्यय करने प्रवृत्ति अधिक उच्च होती है (सरकार ऐसी ही एक बड़ी आर्थिक इकाई है) तो सकल मांग में अन्ततः एक बड़ी वृद्धि ही दिखाई देने लगेगी।

1.60 किन्तु यह अपेक्षाकृत सुखद परिणाम तभी संभव हो पाएगा जब हम तेजी से अर्थव्यवस्था का पुनःमुद्रीकरण कर लें। अन्यथा ऐसा नहीं हो पाएगा (रेखाचित्र 9ख दर्शा चुका है कि वर्ष के अंत तक विनिमय मांग के लगभग 90 प्रतिशत अंश की पूर्ति होने लगेगी)। साथ ही अनिश्चितता दूर करने के लिए उपयुक्त नीतियां अपनानी होंगी तथा अतिउग्र कर प्रशासकों पर भी अंकुश लगाना होगा। तभी विमुद्रीकरण के दुष्प्रभाव गैर स्थायी स्वरूप धारण कर पाएंगे।

1.61 और अन्त में, विमुद्रीकरण नकदी एवं मुद्रा के अन्य स्वरूपों के बीच प्रतिस्थापनीयता का एक स्वभाविक प्रयोग सिद्ध होगा। इसने इन दो स्वरूपों की आपूर्तियों के बीच एक बड़ी खाई निर्मित कर दी है। यदि नकदी और अन्य स्वरूपों में प्रतिस्थापनीयता हो तो इस खाई का प्रभाव क्षीण पड़ जाएगा। यदि दूसरी ओर नकद की प्रतिस्थापनीयता नहीं हो पाई तो प्रभाव अधिक गहन हो जाएगा।

V. वर्ष 2017-18 की आशाएं

(क) वास्तविक जीडीपी

1.62 आइए, अब 2017-18 की आशाओं की ओर दृष्टि डालें। हमें सकल मांग के प्रत्येक घटक पर विचार करना होगा : निर्यात, उपभोग, निजी निवेश और सरकारी व्यय पर।

1.63 जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, भारत के निर्यात में वृद्धि का क्रम प्रारंभ हो चुका है और इसका कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में हो रहा उन्नयन है। यह क्रम अमेरिकी चुनाव और प्रत्याशित राजकोषीय उत्प्रेरणा के बाद भी चलता रहेगा। जनवरी में IMF ने अपने विश्व आर्थिक संभावना पूर्वाकलन को संशोधित किया है। इसमें 2016 के 3.1 प्रतिशत से सुधार कर 2017 में विश्व संवृद्धि दर के 3.4 प्रतिशत होने की आशा व्यक्त की

गई है। इसी अवधि में विकसित देशों की संवृद्धि दर के भी 1.6 से बढ़कर 1.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। भारत की वास्तविक निर्यात की वैश्विक जीडीपी के प्रति लोच अधिक होने के कारण यह अपेक्षा की जा रही है कि निर्यात में होने वाली वृद्धि अगले वर्ष देश की आर्थिक संवृद्धि दर में 1 प्रतिशत बिन्दु का योगदान और देगी।

1.64 निजी उपभोग को लेकर अपेक्षाएं इतनी स्पष्ट नहीं हैं। विश्व में तेल कीमतें 2016 की अपेक्षा 10 से 15 प्रतिशत अधिक रहने की आशंका है। यह संवृद्धि में 0.5 प्रतिशत क्षति कर सकती है। दूसरी ओर दो कारणों से इस उपभोग में वृद्धि भी संभव है : एक तो विमुद्रीकरण के कारण आई शिथिलता (वर्ष 2016-17 के उत्तरार्द्ध की दो तिमाहियों के दौरान) का निवारण एक सामान्य प्रक्रिया होगा; और दूसरे 2017 में उधार की लागतें 75 से 100 आधारिक बिन्दु कम रहने से भी इस उपभोग (विशेषकर दीर्घोपयोगी वस्तुओं पर व्यय) को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर गृह निर्माण, उपभोक्ता दीर्घोपयोगी पदार्थों और अर्द्ध दीर्घोपयोगी चीजों पर व्यय में शानदार वृद्धि होने की आशा है। वर्ष 2017 के मानसून की भविष्यवाणी करना तो अभी जल्दबाजी होगी, इसी कारण कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान भी कठिन है। किन्तु इस वर्ष कृषि उत्पाद संवृद्धि दर अधिक रही है। अतः अगले वर्ष इसमें और तीव्र वृद्धि की संभावना कम ही आंकनी चाहिए।

1.65 फिर, अभी तक दोहरी तुलनपत्र प्रणाली की समस्या का कोई व्यवहारिक समाधान नहीं उभर पाया है। अतः निवेश स्तर में वित्त वर्ष 2017 की अपेक्षा बहुत बड़े सुधार की आशा कर पाना कठिन ही है। इस त्रुटि का आंशिक समाधान तो उच्चतर सार्वजनिक निवेश द्वारा हो सकता है, किन्तु वह भी राजकोषीय नीति के दृष्टिकोण पर निर्भर होगा, उसके समक्ष विमुद्रीकरण के संक्षोभ से उबर रही अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक आवश्यकताओं तथा मध्यकालिक वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बीच संतुलन बिठाने और ऐसा करते हुए दिखने की चुनौतियां तो विद्यमान हैं ही।

1.66 इन सभी कारकों पर विचार करते हुए हम वित्त वर्ष 2018 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के 6 3/4 से 7 1/2 प्रतिशत के बीच रहने की अपेक्षा कर सकते हैं। इस पूर्वाकलन में भी भारत विश्व की तीव्रतम संवृद्धिशील बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

1.67 इस पूर्वकलन को कम कर सकने वाली तीन जोखिमों भी विद्यमान हैं। पहली बात तो यह है कि विमुद्रीकरण के शिथिलताकारी प्रभाव किसी सीमा तक अगले वर्ष भी बने रहेंगे (विशेषकर यदि नीति स्तर पर अस्पष्टता ही छाई रही)। करेंसी की कमी कुछ कृषि उत्पादों, विशेषकर दूध की आपूर्ति को प्रभावित करती है (हम विभिन्न एजेंसियों द्वारा दुग्ध प्रापण में कमी देख रहे हैं), चीनी (जहां कुछ दक्षिणी राज्यों में गन्ने के उत्पादन पर सूखे का प्रभाव पड़ा है) और आलू तथा प्याज की बुआई-रोपाई भी शिथिल रही है। इस बात पर सतर्कता रखनी होगी कि कहीं अन्य कृषि उत्पादों को लेकर आपूर्ति की बाधाएं 2017-18 में उसी स्थिति का निर्माण नहीं कर दें जो 2015-16 में दालों को लेकर पैदा हो गई थी।

1.68 विश्व राजनीतिक उतार चढ़ाव तेल कीमतों को हमारे अनुमान से अधिक स्तर तक ले जा सकता है। शेल तेल उत्पादन में तुरन्त वृद्धि की संभावनाएं अधिक तीव्र वृद्धि की आशंका का निवारण कर सकती हैं। किन्तु, यदि तेल कीमतें मात्र \$60-65 प्रति बैरल तक भी पहुँच गईं तो भारत में उपभोग में कमी, सार्वजनिक निवेश की क्षीण संभावना और कंपनियों के लाभ में कमी होने के फलस्वरूप निजी निवेश व्यय पर और आघात होने की आशंकाएं हो सकती हैं। यदि उच्च तेल कीमतों से स्फीति की आशंका हुई तो मौद्रिक नीति में अधिक उदारता की संभावना नहीं बचेगी।

1.69 तीसरी बड़ी नकारात्मक संभावना बड़े देशों के बीच राजनीतिक उथल-पुथल या फिर करेंसी की विनिमय दरों के कारण भी व्यापार में तनाव पैदा हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक संवृद्धि दुष्प्रभावित होगी और उदीप्यमान अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी का पलायन प्रारंभ हो जाएगा।

1.70 एक महत्वपूर्ण शुभ संभावना विश्व स्तर पर मांग में उछाल है। उससे भारत का निर्यात भी बेहतर होगा। इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण पिछली दो तिमाहियों में दिखाई भी पड़े हैं। निर्यात में अच्छे सुधार का निवेश पर एक व्यापक प्रतिच्छालन प्रभाव होगा।

(ख) राजकोषीय संभावनाएं

1.71 अगले वर्ष केन्द्रीय सरकार के लिए राजकोषीय संभावनाएं तीन कारकों से प्रभावित रहेंगी। सबसे पहले

तो पिछले दो वर्षों से तेल कीमतों के प्रभाव से संभव हो रही कर जीडीपी अनुपात में 0.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि तो विलुप्त होने वाली है। वस्तुतः उत्पादन शुल्क आदि करों में जीडीपी के अनुपात के रूप में 0.1 प्रतिशत की गिरावट ही होगी। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2017 की अपेक्षा जीडीपी के 0.6 प्रतिशत अंश की कर संग्रह में कटौती की आशंका है।

1.72 दूसरे, बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक में जमा नहीं कराए गए उच्च मूल्य नोटों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पोषित आय पर करों के रूप में एक बड़ी राजकोषीय प्राप्ति संभावित है। लेकिन ये एक बार ही हो जाने वाली घटनाएं हैं तथा इनकी प्राप्ति भी अनिश्चित ही है।

1.73 तीसरा कारक जीएसटी लागू होना है। संभावना यही है कि इसका क्रियान्वयन वर्ष के अगले कुछ महीनों में ही हो जाएगा। प्रशासकीय और प्रौद्योगिकीय पटलों पर जीएसटी का क्रियान्वयन इतनी जटिलताओं से भरा है कि इसके माध्यम से राजस्व संकलन की पूरी संभावनाओं के प्रस्फुटन में काफी समय लग सकता है। जब इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि केन्द्र ने जीएसटी के कारण राज्यों के राजस्व में संभावित गिरावट (-14 प्रतिशत वृद्धि को सामान्य मानकर) की प्रतिपूर्ति करने का भी आश्वासन दिया है, तो केन्द्रीय राजकोष की अवस्था को लेकर सावधानीपूर्वक ही पूर्वानुमान बनाने होंगे। जीएसटी और विमुद्रीकरण से राजकोषीय लाभ होंगे तो अवश्य, किन्तु उनके होने में समय लग सकता है।

1.74 साथ ही गैर कर राजस्व में शिथिलता और 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू करने हेतु अनुदान भी राजकोषीय घाटे को ऊपर उठा सकते हैं।

(ग) वर्ष 2017-18 के लिए समष्टि आर्थिक नीति पक्ष

1.75 विमुद्रीकरण के संक्षोभ से उबर रही अर्थव्यवस्था को नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होगी। यदि मान लें कि नकद जीडीपी अनुपात 8 नवंबर 2016 के स्तर से नीचे आ जाएगा तो बैंक क्षेत्रक जमाओं के उच्चतर स्तर से लाभान्वित होगा। अतः बाजार में सभी ब्याज दरें, चाहे जमा पर हों या उधार पर तथा सरकारी निक्षेपों पर प्रति प्राप्ति की दरें 2016-17 की अपेक्षा 2017-18 में निम्न ही रहेंगी। इससे अर्थव्यवस्था को एक प्रोत्साहन मिलेगा

(बस तरलता एक संरोध नहीं बन जाए)। इसकी एक उत्पत्ति है : नीति निर्धारित दरें कम होनी चाहिए, बाजार दरों को कमी की ओर धकेलने के लिए नहीं बल्कि उनमें आ रही कमी का समर्थन करने के लिए। हां यह बात सत्य है कि तेल कीमतों और कृषिक उत्पादों की कीमतों में बड़े उछाल दिखाई दिए तो मौद्रिक स्तर पर मृदुलता अपनाने की संभावनाएं कम रह जाएंगी।

1.76 राजकोषीय नीति भी सहारा और समर्थन दे सकती है। इस वर्ष के तर्क पिछले वर्ष से दो प्रकार से कुछ भिन्न हैं। पिछले वर्षों के विपरीत इस बार विमुद्रीकरण के कारण कुछ अधिक 'दुर्बलता' की झलक मिल रही है। साथ ही तीन वर्षों से लगातार राजकोषीय पटल पर संगतिपूर्ण सुधारों के माध्यम से सरकार ने अधिक विश्वस्तता अर्जित की है। केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा 2013 में जीडीपी का 4.5 प्रतिशत था। यह घटते हुए 4.1, 3.9, 3.5 प्रतिशत तक पहुँच गया है। किन्तु राजकोषीय नीति को चक्रीय अपरिहार्यताओं और सूझबूझ तथा विश्वस्तता की मध्यमकालिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

1.77 अप्रत्याशित आय (जो नोट लौटाए नहीं गए तथा PMGKY के अंतर्गत प्राप्ति) का प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा (वैसे अभी तक इन मदों से प्राप्त आय को लेकर असमंजस ही है)। किन्तु ये अप्रत्याशित प्राप्ति एक ही बार होने वाली है, इसका स्वरूप संपदा प्राप्ति है, आय की वृद्धि नहीं। अतः उचित तो यही होगा कि इसका प्रयोग सरकार के तुलनपत्र को सुदृढ़ करने के लिए किया जाए, ऐसे सरकारी उपभोग में तो किसी भी हालत में नहीं जो स्थायी अधिकारिताओं का सृजन कर देता हो। अतः, इन परिस्थितियों में अप्रत्याशित आय का श्रेष्ठतम सदुपयोग एक सार्वजनिक क्षेत्रीय परिसंपदा निर्माण कंपनी (अध्याय-4 में चर्चित) का गठन होगा। यह दोहरे तुलनपत्र की समस्या का समाधान कर पाएगी, साख सुलभ करा निवेश को पुनः प्रोत्साहित करेगी या फिर जीएसटी प्रतिपूर्ति कोष की स्थापना द्वारा कर की दरें घटाने और न्याय संगत बनाने में सहायक होगी, या कम से कम इस राशि का प्रयोग सरकार के ऋण भार को कम करने के लिए तो होना ही चाहिए। इस अनायास मिली राशि का राजकोषीय नीति के संचालन में प्रगति विषयक निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

1.78 संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले श्रेष्ठ सुधार संभवतः संरचनात्मक सुधार ही होंगे। अनुच्छेद-1 में चर्चित सुधारों के यौक्तिक विनिवेश, कर-सुधार, सब्सिडी को तर्क संगत बनाने के साथ-साथ दोहरी तुलनपत्र समस्या का भी प्रत्यक्ष रूप से समाधान खोजना होगा। अध्याय-4 स्पष्ट कर रहा है कि यह समस्या बहुत बड़ी है, लगातार बनी हुई है और कठिन भी है। यह अपने आप सुलझने वाली भी नहीं है, चाहे संवृद्धि दर में सुधार हो या ब्याज दरें कम हो जाए, वस्तुतः अभी तक इसके समाधान के सभी प्रयास नितांत अपर्याप्त ही सिद्ध हुए हैं। संभवतः अब वह समय आ गया है जब एक सार्वजनिक परिसंपदा पुनः निर्माण कंपनी का गठन होना ही चाहिए।

1.79 सुधारों का एक अन्य आयाम श्रम से जुड़ा है। श्रम कानूनों में बड़ा परिवर्तन तो मुश्किल लगता है किन्तु श्रमिकों को अधिक चयन के अवसर सुलभ कराने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। इससे सेवा प्रदाताओं के बीच स्पर्धा में वृद्धि होगी। इन चयनों का स्वरूप यह हो सकता है : क्या वे कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (EPFO) में अपना अंश भाग जमा करना चाहते हैं या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) अथवा किसी वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कम से कम केंद्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन कागजी कारवाई की जटिलता से मुक्त हो जाए, इसके क्रियान्वयन में नकदी का चलन भी नहीं रहे।

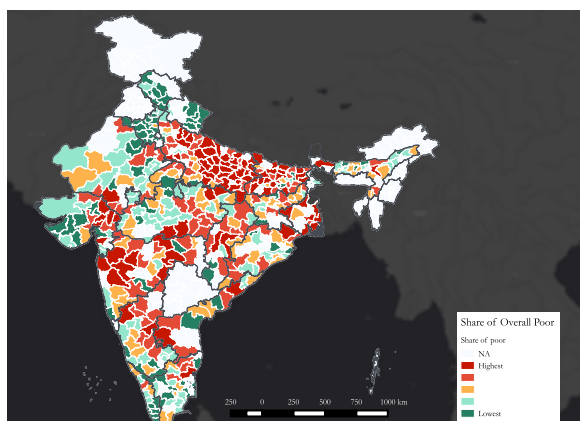
1.80 व्यय पक्ष पर अध्याय-9 में चर्चा होगी और वहां स्पष्ट किया जाएगा कि वर्तमान सरकारी कार्यक्रमों के लाभ वास्तविक लक्षित वर्गों तक नहीं पहुंच पाते। एक क्रांतिकारी विचार तो सार्वलौकिक आधार आय स्तर व्यवस्था को अपनाना है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। किन्तु एक कहीं अधिक उदारतापूर्ण प्रस्ताव है कि नए सरकारी व्यय कार्य अभी प्रारंभ नहीं किए जाएं; यदि किसी पुराने कार्य जैसा ही प्रस्ताव हो तो उसकी यह पूर्व समीक्षा अवश्य हो कि नया प्रस्ताव किस प्रकार पुराने कार्यक्रम की त्रुटियों को दूर करेगा; और साथ ही अपने ध्येय प्राप्त करने में किल रहे किन्तु अभी तक चल रहे कार्यों को धीरे-धीरे बंद करने की प्रतिबद्धता भी आवश्यक हो रही है।

VI. अन्य मुद्दे

(क) पुनःवितरण : सार्वलौकिक आधारिक आय (UBI) : एक नया क्रांतिकारी बोध

1.81 अध्याय-9 में भारत के पुनःवितरण संबंधी विस्तृत प्रयासों पर चर्चा की जा रही है। केवल केन्द्र सरकार संचालित एवं प्रायोजित पुनःवितरण योजनाओं की संख्या 950 है और इन पर जीडीपी के 5 प्रतिशत के समान लागत आती है। स्पष्टतः अनेक का तर्काधार स्पष्ट दिखाई देता है। किंतु लक्षित करने की प्रभावोत्पादकता में कुछ सीमाएं अंतर्निहित होती हैं। रेखाचित्र 18 आवंटन की त्रुटिपूर्णता स्पष्ट कर रहा है इसमें सबसे बड़े 6 कार्यक्रमों की जानकारी लेकर उसकी तुलना देश के जनपदों में गरीबों के अंशभाग से की गई है (रेखाचित्र 18(क) और उन्हें कम आवंटित धन की बात उठाई गई है (रेखाचित्र 18(ख) में यह कमी या अंतर आवंटित धन अंश और गरीबों के अंश के बीच अंतर द्वारा परिभाषित है)। ये दोनों रेखाचित्र एक बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं : जिन जनपदों में जनसंख्या में गरीबों का अनुपात उच्चतम है, उन्हीं को आवंटित धन राशियां कम रहती हैं। ये जनपद दोनों रेखाचित्रों में लाल रंग द्वारा दिखाए गए हैं। इस प्रकार से आवंटन की गड़बड़ी के गंभीर परिणाम होते हैं : वस्तुतः जिन गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वही इससे वंचित रह जाते हैं, कहीं न कहीं गैर गरीब वर्गों को उन लाभों का क्षरण तथा स्थानीय भ्रष्टाचर द्वारा उक्त लाभ हड़प कर जाना भी समस्या के अन्य स्वरूप हैं। अनेक कार्यक्रमों की प्रमुख समस्या यही है कि उनकी प्रभावोत्पादकता प्रांत की कार्यक्रम स्वीकार

रेखाचित्र 18क : गरीबों का सकल अंश रही

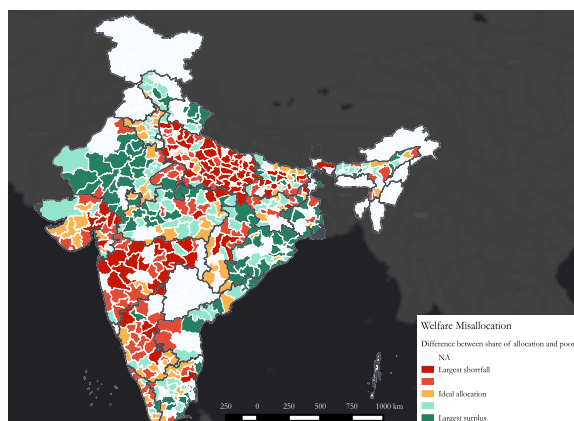


स्रोत: NSS, 2011-12

कर उसे लागू कर पाने की संस्थाबद्ध क्षमताओं पर निर्भर रहती है। तमिलनाडू और आंध्रप्रदेश जैसे प्रांतों में बिहार जितना गरीब जन अनुपात भले ही नहीं हो किंतु उनकी ऐसे कार्यक्रम (केन्द्र द्वारा प्रस्तावित) स्वीकार कर उन्हें लागू करने की क्षमता बिहार से बहुत अधिक है। यह कोई विचित्र बात नहीं है, प्रायः सभी गरीबी निवारण एवं सामाजिक कार्यक्रमों में यही बात अन्तस्थ पाई जाती है। ऐसे मामलों में “बहिष्कृत की जोखिम” अर्थात् सर्वाधिक पात्र जन समुदाय के कार्यक्रम से बाहर रह जाने की जोखिम अधिक रहती है।

1.82 उचित एवं अन्य कारकों के प्रभाव स्वरूप समीक्षा (अध्याय-9 में) यह आग्रह कर रही है कि “प्रत्येक गांव के आसू पोछने” के महात्मा गांधी के आदर्श उद्देश्य की प्राप्ति का कहीं बेहतर माध्यम सार्वलौकिक आधारिक आय सुनिश्चित करने का नवीन विचार हो सकता है। ऐसे UBI प्रकल्प का एक सद्गुण यही है कि यह निम्न स्तर पर कार्यक्रम संचालन करने की क्षमता का आश्रित नहीं होगा। यह तो सभी पात्र जनों को ऊपर से लाभ प्रदान करने पर निर्भर रहेगा। अतः इसमें बहिष्कृति की आशंका कम रह जाएगी। साथ ही यह लाभ राशियां नौकरशाही के अनेक स्तरों को दूर करते हुए सीधे ही लाभान्वितों के बैंक खातों में जमा होने पर इस व्यवस्था में से क्षरण (सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एक अंतरंग विशेषता) की समस्या पर भी अंकुश लग सकता है। हां, इस मार्ग में अनेक क्रियान्वयन स्तर की बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर चिन्तन-मनन होना बाकी है। अध्याय-9 अनेक मार्ग सुझा रहा है, प्रत्येक की अपनी-अपनी कठिनाइयां भी हैं।

रेखाचित्र 18ख: गरीबों को आवंटन में कमी



स्रोत: भारत सरकार और NSS 2011-12

किन्तु राजनीतिक पटल पर सभी पक्षों की इस विषय में वैचारिक सहमति सुझा रही है कि इस विचार का शीघ्र ही व्यवहारिक नीति विमर्श में समावेश होना चाहिए।

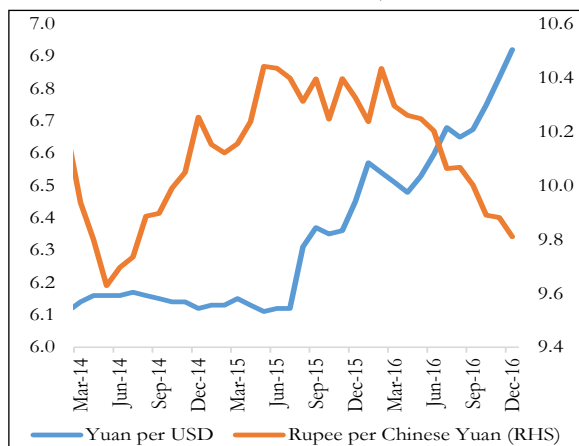
(ख) विनिमय दर नीति : चौकसी और निगरानी की नई विधियां

1.83 वैश्विक वित्तीय संकट, यूरो क्षेत्रीय संकट और चीन के 2015 के आशंकाग्रस्त घटनाक्रमों के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर कम हो रहे हैं। हमने बॉक्स-2 में भी दिखाया था कि 2011 से लेकर निर्यात जीडीपी अनुपात कम हो रहा है और आगे डालर में तीखी वृद्धि अपेक्षित है, जिससे भारत, चीन, वियतनाम जैसे देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों में गिरावट आएगी। जुलाई 2015 के बाद से ही युआन (दिसंबर 2016 में) लगभग 1.6 प्रतिशत गिर चुका है। परिणाम स्वरूप भारतीय रूपया युआन की तुलना में 6 प्रतिशत ऊपर हो गया है (रेखाचित्र 19)। पुनःसंतुलन की युक्ति को स्थगित रखने की नीति से आगे भी करैसी में मृदुलता बनी रहगी। यदि पूंजी के बाहर की ओर प्रवाह बने रहे तो यह मृदुलता अवश्यंभावी हो जाएगी (देखें आर्थिक समीक्षा, 2016, बॉक्स-1)।

1.84 निर्यात में अच्छी वृद्धि दर को बनाए रख पाना भारत के लिए जरूरी है। इसीलिए विश्व बाजार में भारतीय निर्यात की स्पर्धाशीलता का आंकलन आवश्यक है।

1.85 भारत की स्पर्धा क्षमता की पुनः समीक्षा करने का एक अन्य कारण भी है- वियतनाम, बंगलादेश और

रेखाचित्र 19 : युआन-डालर तथा रूपए-युआन की परस्पर विनिमय दरें



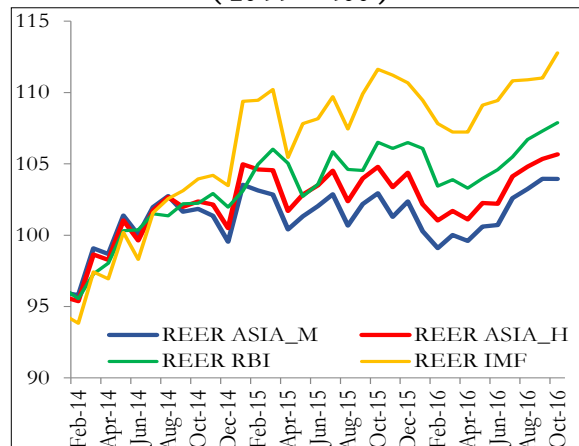
स्रोत: आरबीआई

फिलिपीन्स जैसे देश अनेक उत्पादों और सेवाओं में भारत के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर रहे हैं।

1.86 क्या भारत ने अभी तक विनिमय दर को स्पर्धाशील बनाए रखा है और भविष्य में क्या करना आवश्यक होगा?

1.87 वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के आंकड़ों पर निगाह डालते ही स्पष्ट हो जाता है कि 2013 के संकट के बाद से भारतीय रूपए के मान में 19.4 प्रतिशत का सुधार हुआ है (यह जनवरी 2014 से अक्टूबर 2016 के बीच की तुलना है)। यह आंकलन IMF ने किया है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकलन के अनुसार यह सुधार 12 प्रतिशत रहा है। किन्तु ये दोनों सूचक कुछ भ्रामक हो सकते हैं। संयुक्त अरब गणराज्य भारत का तेल आयात का एक प्रमुख स्रोत है और यहीं से अन्य देशों को भारतीय निर्यात होते हैं। इसी नाते रिजर्व बैंक के आंकलन में इस देश को अधिक भारमान प्रदान किया गया है। किन्तु इस व्यापार का स्पर्धाशीलता से शायद ही कुछ नाता हो। रिजर्व बैंक और IMF दोनों का ध्यान सकल व्यापार पर रहता है, केवल विनिर्माण व्यापार पर नहीं। जबकि अनेक नीतियों की दृष्टि से तो श्रम-सघन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उपयोगी होगा। परिणाम स्वरूप हम यूरो को अधिक भारमान प्रदान कर बैठते हैं, जबकि हमारे वास्तविक स्पर्धी तो यूरोपवासी नहीं बल्कि एशियाई देश ही हैं।

1.88 अतः हम भारत के विनिर्माण प्रतिद्वंद्वियों पर रेखाचित्र 20 : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर तुलनाएं (2014 = 100)



स्रोत: आरबीआई

केन्द्रित एक नवीन वास्तविक विनिमय दर सूचक की रचना कर रहे हैं। मूलतः हम उन देशों को अधिक भारमान प्रदान कर रहे हैं जो विश्व वित्तीय संकट के बाद से विनिर्माण में बहुत अधिक स्पर्धी हो गए हैं। यह विश्व निर्यात बाजार में उनके अंशभाग से सहज स्पष्ट हो जाता है। इस सूचक की रचना का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। यहां तो हम केवल निष्कर्ष बता रहे हैं। रेखाचित्र 20 में IMF और रिजर्व बैंक के (36 करेंसी आधारित) सूचकों की हमारे आंकलित दो सूचकों से तुलना की गई है। एक REERASIA-M में हमने भारत के प्रतिद्वंद्वी (चीन, वियतनाम और फिलिपीन्स) देशों को कुछ उच्च भारमान दिया है तो दूसरे REER-ASIA-H में उन्हें अधिक उच्च भार प्रदान किया गया है। यही देश हैं; जिनका विश्व बाजार अंश 2010 के बाद से अधिक हो गया है।

1.89 यह आश्चर्यजनक जानकारी स्पष्ट हो रही है कि IMF और रिजर्व बैंक, दोनों ही 2014 से रूपए की स्थिति में सुधार का कहीं अधिक आंकलन कर रहे हैं। इसका मूल कारण उन द्वारा यूरो (जो सारी अवधि में दुर्बलताग्रस्त रहा है) को अधिक भारमान दिया जाना ही है। जब अपेक्षाकृत सुदृढ़ रही एशियाई करेंसियों से तुलना करते हैं तो REERASIA-M और NEERASIA-H दोनों ही दिखाते हैं कि स्पर्धाशीलता की हानि क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत ही रही है (जनवरी 2014 से अक्टूबर 2016 के बीच)।

1.90 दूसरे शब्दों में, व्यापार भागीदार देशों से अधिक पूंजी प्रवाह पाते हुए और उच्चतर स्फीति के बावजूद भारत ने अपने निर्यात को स्पर्धाशील बनाए रखने में सफलता पाई है। वर्ष 2010 से 2015 के बीच विश्व बाजार में भारत के विनिर्मित निर्यात अंश में वृद्धि इसी बात को प्रमाणित करती है।

1.91 किन्तु यदि और आगे की ओर देखें तो IMF का आधार स्तर मापक बिल्कुल विपरीत दिशा में भ्रामक परिदृश्य की रचना कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि युआन और अन्य एशियाई देशों की मुद्राएं डालर की अपेक्षा कमजोर पड़ जाएं किन्तु अन्य विनिमय दरें, विशेषकर डालर यूरो दर में अधिक बदलाव न हो (इस समय यूरो को अत्यंत निम्न स्तर पर आंका जा रहा है,

अतः यह सहज संभव है) तो फिर एशियाई मुद्राओं का अधो-आंकलन करने वाला IMF का सूचक यह भ्रम पैदा कर देगा कि भारतीय रूपए की दर स्पर्धी है, जबकि वास्तव में इसमें ह्रास हो रहा होगा। अतः नीति पटल पर इसका एक ही निहित अर्थ है : यदि भारत सचमुच निर्यात स्पर्धी बने रहना चाहता है और इसे एशियाई निर्यातकों को लेकर चिंता है तो इसे उस विनिमय दर सूचक पर ध्यान देना होगा जो इन स्पर्धी देशों की मुद्राओं को अधिक भारमान प्रदान करता है।

(ग) व्यापार नीति

1.92 ब्रेक्जिट और अमेरिकी चुनाव के बाद से विश्व व्यापार नीति विमर्श में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अमेरिका में समष्टि आर्थिक परिवर्तन और बल धारण करेंगे तथा डालर में सुधार की वर्तमान प्रक्रिया और सशक्त होगी। 8 नवंबर, 2016 से दिसंबर अंत तक डालर में 5.3 प्रतिशत का उछाल आया और इसने जनवरी 2017 में ही अपने व्यापार भागीदारों के मौद्रिक सूचक के आधार पर और 3.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है। अमेरिकी व्यापार नीतियों का इतिहास है कि 1950 के दशक मध्य में इनका सबसे अधिक संरक्षणवादी स्वरूप उभर कर आया था और उस समय भी मौद्रिक नीति में कड़ाई तथा राजकोषीय नीति में उदारता की जा रही थी।

1.93 विकसित देशों में संरक्षणवादी दबावों और भारत जैसे देशों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए विश्व बाजारों के खुलेपन की जरूरतें देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि भारत एवं शेष उदीप्यमान देश मिलकर विश्व बाजार को खुला बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। विश्व व्यापार नेतृत्व में एक खालीपन की रचना हो रही है और आवश्यक हो रहा है कि निर्बन्ध व्यापार के पक्ष में भारत का स्वर और बुलंद हो तथा वह अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उस नेतृत्व का दायित्व संभालने में संकोच नहीं करे। हां, इसके लिए भारत को अपने बाजार को और उदार बनाना होगा अर्थात् अपनी निर्बन्धता का आरंभ अपने घर से करना होगा।

1.94 यहां दो विशेष सुयोग उभर कर आ रहे हैं। हमारा अध्याय-7 भारत के लिए श्रम सघन निर्यात संवर्धन की अनिवार्यता दर्शा रहा है। अतः भारत को सक्रिय रूप से ब्रिटेन और यूरोप के साथ निर्बन्ध व्यापार अनुबंधों पर

तालिका 1 : EU तथा UK के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से अधिक निर्यात एवं रोजगार की संभावनाएं

	परिधान		चमड़े की वस्तुएं		जूते चप्पल	
	अतिरिक्त निर्यात (\$मिलियन)	रोजगार में वृद्धि (संख्या)	अतिरिक्त निर्यात (\$मिलियन)	रोजगार में वृद्धि (संख्या)	अतिरिक्त निर्यात (\$मिलियन)	रोजगार में वृद्धि (संख्या)
ईयू	1483.6	76853	416.9	18542	216.9	9966
यूके	603.3	31176	103.8	4615	95.3	4381
योग	2086.9	108029	520.7	23156	312.2	14347

स्रोत: समीक्षा गणना

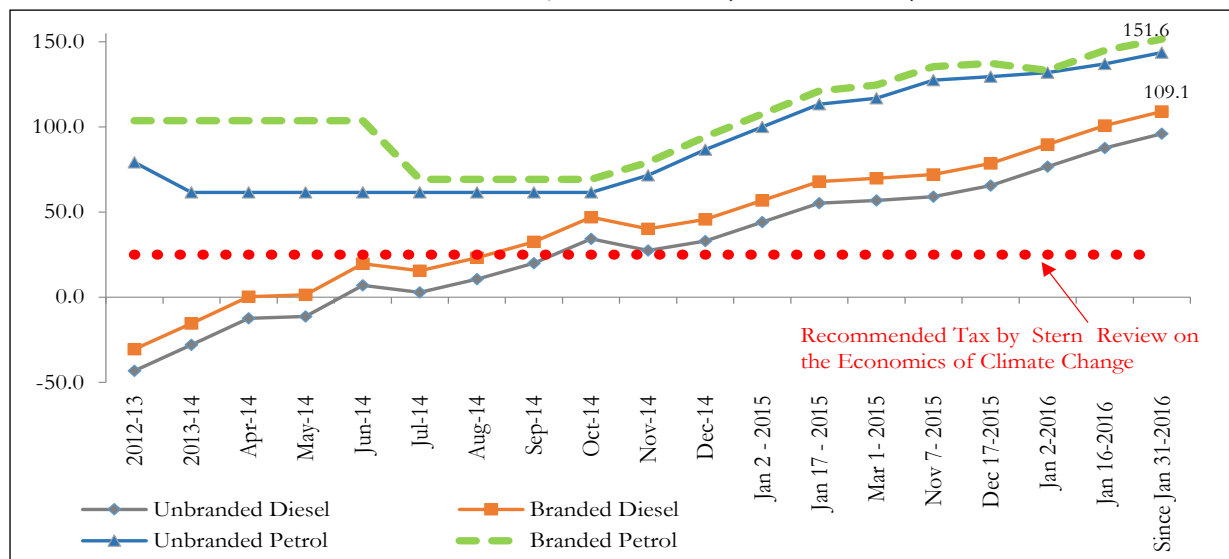
वार्तालाप करना चाहिए। यहां निर्यात और देश में रोजगार वृद्धि की संभावनाएं बहुत विशाल हैं। पिछले वर्ष की समीक्षा में प्रारंभ किए गए चिन्तन मनन के आधार पर हमारा आकलन है कि केवल परिधान, चर्म और जूतों का निर्यात \$3 बिलियन बढ़ाया जा सकता है, साथ ही इससे 1.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे (तालिका 1)।

1.95 साथ ही यह भी संभव है कि एशिया में प्रशांत क्षेत्रीय भागीदारी (TPP) तथा यूरोपीय संघ से एटलांटिक व्यापार एवं निवेश भागीदारी जैसी क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं से अमेरिका के पीछे हटने के कारण विश्व व्यापार संगठन का महत्व और प्रासंगिकता और अधिक हो जाएगी। भू-राजनीतिक बदलावों के परिवेश में एक बड़े भागीदार होने के कारण विश्व व्यापार संगठन और बहुराष्ट्रवाद

को पुनः जीवित करने की दिशा में भारत को अधिक सक्रिय प्रयास करने होंगे।

(घ) मौसम में परिवर्तन और भारत

1.96 दिसंबर 2015 की मौसम परिवर्तन संधि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नवीन उत्कृष्ट उदाहरण है। अब सारा ध्यान इस संधि की व्यवस्थाओं को लागू करने की ओर रहेगा। मौसम परिवर्तन की समस्या के समाधान में कार्बन उत्सर्जन की कीमत के निर्णायक महत्व को लेकर पहले ही व्यापक स्तर पर सहमति बन चुकी है (स्टर्न, 2006, विट्समैन, 2007 और नॉर्बास)। भारत का अभी तक इस दिशा में क्या निष्पादन रहा है? जून 2014 से पेट्रोलियम कीमतों में भारी गिरावट के कारण मौसम परिवर्तन को रोकने की दिशा में

रेखाचित्र 21 : निहित कार्बन कर (\$/t of CO₂)

स्रोत: समीक्षा की गणनाएं

तालिका 2 : मुख्य देशों में स्थानीय पेट्रोलियम कर (डॉलर प्रति लीटर)

क्रमांक	देश	डीजल				पेट्रोल			
		जून-14	जन-16	नवंबर-16	प्रतिशत परिवर्तन (जून 2014 से नवंबर 2016 तक)	जून-14	जन-16	नवंबर-16	प्रतिशत परिवर्तन (जून 2014 से नवंबर 2016 तक)
1	भारत	0.00	0.38	0.38	large no	0.21	0.54	0.53	152.3
2	अमेरिका	0.13	0.14	0.14	5.4	0.11	0.12	0.12	6.3
3	चीन	0.30	0.28	0.28	-6.7	0.32	0.34	0.34	6.3
4	जापान	0.39	0.34	0.35	-9.7	0.63	0.55	0.57	-8.9
5	कनाडा	0.29	0.21	0.23	-21.2	0.37	0.27	0.29	-21.2
6	फ्रांस	0.60	0.74	0.75	25.1	1.18	0.93	0.92	-22.0
7	जर्मनी	0.64	0.68	0.69	8.0	1.24	0.93	0.92	-25.5
8	इटली	0.84	0.91	0.91	8.0	1.42	1.07	1.05	-26.2
9	स्पेन	0.50	0.58	0.59	17.0	0.97	0.71	0.71	-26.9
10	यू.के.	0.98	1.08	0.97	-1.1	1.35	1.08	0.96	-28.8

स्रोत: जी 7 देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (<http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/>) अन्यथा वित्त मंत्रालय के अनुमान।

प्रयासों को पहुँचते गहरे आघात की दृष्टि से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन चुका है।

1.97 तालिका-2 तथा रेखाचित्र 21 में उपर्युक्त प्रश्नों के कुछ उत्तर मिल रहे हैं। जून 2014 में पेट्रोलियम कीमतों में कमी आरंभ होने से लेकर दिसंबर 2016 तक भारत ने ब्रांड नाम से विक्रित पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क को रूपए 15.5 से बढ़ाकर 22.7 तथा ब्रांड नाम के डीजल पर रू. 5.8 से बढ़ाकर रू. 19.7 तक पहुँचा दिया है। तालिका 2 में बड़े जी-20 देशों में मौसम परिवर्तन विरोधी प्रयासों का परिमाण निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं।

1.98 भारत में तो पेट्रोल कर को डेढ़ गुना किया गया है, जबकि अधिकांश विकसित देशों ने कीमत में कमी का प्रभाव उपभोक्ता तक पहुँचा दिया है। उनके इस कदम से मौसम परिवर्तन क्रम को रोकने के प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। परिणाम स्वरूप अब भारत यूरोपीय देशों को छोड़ पेट्रोल और डीजल पर कर लगाने में सबसे आगे निकल चुका है।

1.99 रेखाचित्र 21 भारत द्वारा उठाए कदमों में निहित कार्बन कर का आंकलन कर रहा है। अब कार्बन सब्सिडी की व्यवहारिक व्यवस्था को त्याग कर भारत लगभग \$150 प्रति टन की दर से कार्बन कर लगा रहा है। यह

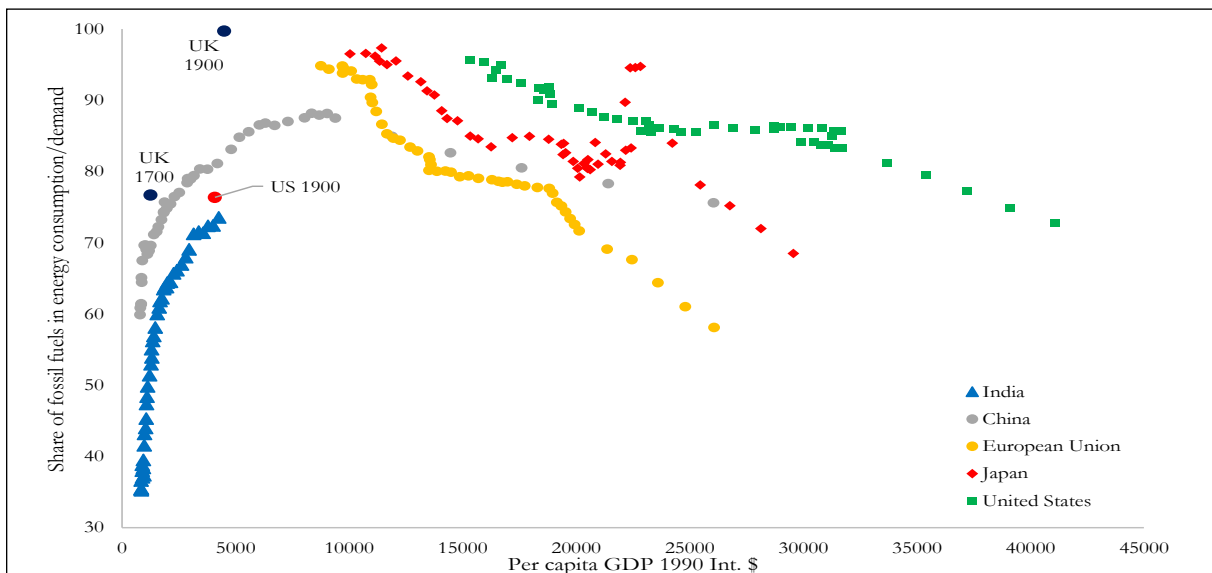
स्टर्न मौसम परिवर्तन समीक्षा की सिफारिश से 6 गुना अधिक है।

1.100 और अन्त में, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में भी भारत के जीवाश्मीय ईंधन प्रयोग पर विचार होना चाहिए। आज सकल ऊर्जा उपभोग में भारत का जीवाश्म ईंधन प्रयोग अंश विकास की तुल्य स्थिति से गुजरे अन्य देशों की अपेक्षा कितना है? रेखाचित्र 22 में इस जानकारी को क्रय शक्ति तुल्य प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर अंकित किया गया है। अभी तक और कल्पनीय भविष्य में भी भारत की यह जीवाश्म ईंधन अनुपात अपने निकटतम तुलनीय देश चीन से ही नहीं बल्कि विकास की तुल्य अवस्था में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप से भी कम रहा है (और रहेगा)। यह भारत द्वारा हीलिंगडम में व्यक्त प्रतिबद्धता कि हम प्रति व्यक्ति स्तर पर विकसित देशों से अधिक उत्सर्जन नहीं करेंगे को ही प्रमाणित कर रहा है। हां आगे की ओर देखें तो भारत को इस वक्र को और झुका कर अन्य देशों से नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि विश्व मौसम परिवर्तन के पटल पर भी यह अच्छे नागरिक का मान-सम्मान बनाए रख सके।

(च) महिलाओं का एकान्त निश्चित करना

101. पिछले दो वर्षों से आर्थिक समीक्षा निरंतर एक नारी विषयक आयाम पर ध्यान दिलाती रही है।

रेखाचित्र 22 : ऊर्जा की सकल मांग/उपभोग में जीवाष्मीय ईंधन का अंश और प्रति व्यक्ति जीडीपी (1971-2040)



स्रोत : जीवाष्म ईंधन के पूर्वाकलित अंश (TPED में) 2020, 2025, 2030, 2035 और 2040 के लिए विश्व ऊर्जा संभावना, 2016 के आंकड़ों के आधार पर आंकलित हैं, इनमें कोयला, तेल और गैस विषयक नवीन नीति परिदृश्य को प्रतिव्यक्ति जीडीपी के साथ रखा गया है। यह मैडिडसन प्रकल्प, 2013 का संस्करण उपलब्ध है : <http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm>, 2013 version. यूरोपीय संघ की जीडीपी के उपर्युक्त स्रोत से आंकलन में माल्टा, साइप्रस और लक्सम्बर्ग सम्मिलित नहीं हैं।

वर्ष 1971 से अभी तक ऊर्जा उपभोग में जीवाष्म ईंधन की जानकारी विश्व बैंक से उपलब्ध है।

सं.रा. अमेरिका की यही जानकारी US Energy Information Administration/ Annual Energy Review 2011 से ली गई है।

ब्रिटेन के जीवाष्म ईंधन उपभोग की जानकारी का स्रोत Warde (2007)⁸ है।

वित्त वर्ष 2015 में परिवार नियोजन विधियां अपनाए जाने में नारी के विरुद्ध हिंसा (जोर जबर्दस्ती) की ओर ध्यानाकर्षण किया गया था। वर्ष 2016 में “माँ और संतान” पर एक अध्याय ने उनके दीर्घकालिक कुशलक्षेम को सुनिश्चित करने में सरकारी हस्तक्षेप के महत्व पर बल दिया गया था।

1.102 स्वच्छतापूर्ण सामाजिक व्यवहार और स्वस्थता के बीच संबंध तो भली प्रकार निरूपित हो चुका है (स्पीअर्स और कनिंग्स, 2013)। हमारा यह अनुच्छेद तो यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि स्वच्छता सेवाओं के अभाव का किस प्रकार नारी जगत पर अनावश्यक रूप से अधिक भार पड़ता है।

1.103 नारी पर यह बोझ कई रूप धारण कर सकता है : खुले में शौच के लिए जाने पर जीवन और शारीरिक जोखिम, शौचादि के लिए घर से बाहर जाना न्यूनतम

रखने के लिए भोजन और जल का उपभोग न्यूनतम रखने की विवशता, प्रदूषित जल के कारण महिलाओं और बच्चों की प्रसव संबंधित संक्रमणों से मृत्यु, और अनेक अन्य प्रभाव।

1.104 नारी की निजी स्वच्छता का न केवल उसके स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने शरीर पर अपने नियंत्रण से सुलभ स्वातंत्र्य में भी झलकती है। यह शारीरिक एकांत का एक मौलिक अधिकार भी है। दूसरे शब्दों में इन सुविधाओं का सापेक्ष अभाव नारी वर्ग के लिए एक ‘शुचिता असुरक्षा’ का कारण बन रहा है।

1.105 स्वच्छता-शुचिता सेवाओं की अलभ्यता की जानकारी भी सभी को है। जनगणना, 2011 ने बताया था कि देश की आधी से अधिक जनसंख्या खुले में शौच करने को विवश है। अधिक नवीन जानकारी के अनुसार अब 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को (पेय जल

⁸ Paul Warde (2007), *Energy Consumption in England and Wales: 1500-2000* published by Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Studio sulle Società del Mediterraneo (ISSM)

एवं स्वच्छता मंत्रालय, 2017)⁹ तथा 89 शहरी परिवारों को (NSSO-2016)¹⁰ को शौचालय उपलब्ध हो चुके हैं। ग्रामीण परिवारों के विषय में NSSO-2015 ने मात्र 45 प्रतिशत को यह सुविधा सुलभ बताई थी। कुल मिलाकर 2011 की जनगणना द्वारा बताई गई स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है।¹¹

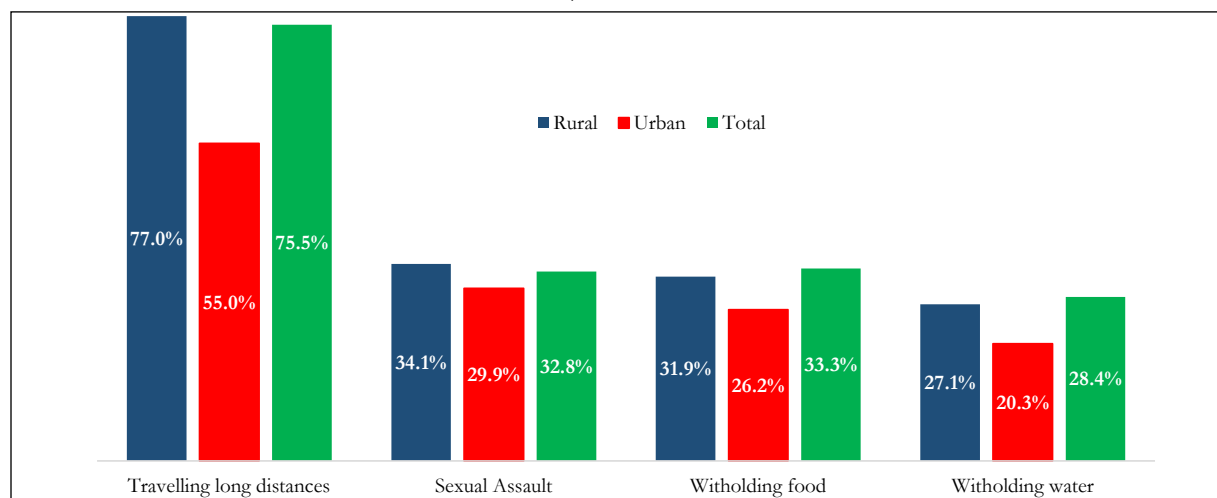
1.106 सामान्य रूप से सुविधाओं के अभाव के कारण महिलाओं के समक्ष और अधिक चुनौतिपूर्ण स्थिति क्यों कर उत्पन्न हो जाती है? वांश संस्थान एवं संबोधी¹² द्वारा 2016 में आर्थिक समीक्षा के लिए किया गया एक अध्ययन इस विषय में विशेष जानकारी प्रदान कर रहा है। उक्त सर्वेक्षण की रूपरेखा का विवरण परिशिष्ट-1 में है। ध्यान रहे कि यहां बताए गए तथ्य किसी कारण प्रभाव संबंध का निरूपण नहीं करते। यह कार्य इस समय चल रहे अध्ययनों द्वारा किया जाएगा।¹³

महिलाओं पर अनावश्यक रूप से भारी बोझा

- शौचालयहीन परिवार : अधिकांश शौचालयहीन

परिवारों के विषय में इस त्वरित सर्वेक्षण ने कुछ चिंताजनक तथ्य उद्घाटित किए हैं, 76 प्रतिशत महिलाओं को शौच सुविधाएं प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक दूर तक चलकर जाना पड़ता है।¹⁴ लगभग 33 प्रतिशत महिलाओं ने एकांताभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक उत्पीड़न तक की समस्याएं होना स्वीकार किया है। इन गंभीर समस्याओं से बचने के लिए प्रतिदर्श में 33 प्रतिशत महिलाओं ने भोजन कम करने तथा 28 प्रतिशत ने तो पानी कम पीने की बात भी स्वीकार की है। यह भोजन एवं जल की कमी न केवल अल्पकाल में रोग बाधाओं और अभावितों का कारण बन जाती है, बल्कि इनसे स्वास्थ्य पर अनेक दीर्घकालिक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, बच्चियों में तो यह विकास क्रम को ही दुष्प्रभावित करने का कारण बन सकता है। अनेक अध्ययनों (सिंह आदि, 2008, कर्टिस एवं मीनास, 1955) ने यह भी बताया है कि खुले में शौचादि कर रहे स्त्री-पुरुषों को केवल प्राकृतिक धूप, बारीश, सर्दी आदि ही नहीं, कितनी ही बार सांप आदि जहरीले जानवरों द्वारा काटे जाने

रेखाचित्र 23 : महिलाओं के लिए शौचालय नहीं होने के संभावित परिणाम



स्रोत: त्वरित समीक्षा (2016)

⁹ Swatchh Bharat Mission website: <http://www.sbm.gov.in>-accessed on 20 January 2016.

¹⁰ Swatchhta Status Report, NSSO, 2016

¹¹ जनगणना 2011 तथा नवीनतम आंकड़ों के अंतर का मुख्य कारण स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में आई तेजी है।

¹² लिंगाधारित मानक और स्वच्छता एवं शुचिता पर एक त्वरित सर्वेक्षण, और जीवन की अवस्था के अनुसार निहितार्थका (किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं), ने 10 राज्यों में 5 प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में स्वच्छता-शुचिता की सुविधाओं का आंकलन किया गया था।

¹³ यहां उद्धृत सभी अनुपात जाति एवं धर्म, गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे की स्थिति, ग्रामीण/शहरी, लिंग तथा परिवार में अपने शौचालय की सुलभता जैसे कारकों के समायोजन के बाद आंकलित किए गए हैं। सभी उद्धृत अंक 95% आश्वसित अंतराल में सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पाए गए हैं।

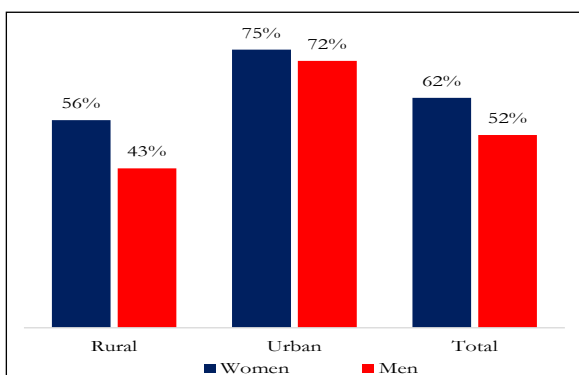
¹⁴ त्वरित सर्वे ने इस अन्तर को व्यक्तियों द्वारा स्वयं बताया गया चर माना है।

के भय का भी सामना करना पड़ जाता है।

- **शौचालययुक्त परिवार :** शौचालय सहित परिवारों में पाया गया है कि महिलाएं इनकी सुविधा का पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रयोग करती हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्हें इनकी अधिक जरूरत होती है। कॉफे आदि (2016) ने पाया था कुछ परिवारों में अनेक कारणों से खुले में शौच के प्रति वरीयता दिखाई देती है (विशेषकर जहां मल आदि एक गड्ढे में ही जमा हो जाता है)। किन्तु त्वरित सर्वे बता रहा है कि शौचालय सहित परिवारों में महिलाओं द्वारा इस सुविधा का प्रयोग अधिक बेहतर ढंग से किया जाता है। यही बात NSSO-2016 ने स्वतंत्र रूप से भी पुष्ट की है। शौचालय युक्त परिवारों की 62 प्रतिशत महिलाएं सदैव उसका प्रयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में सदैव प्रयोग करने वालों का अनुपात 52 प्रतिशत पाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के महिला एवं पुरुषों के सदैव शौचालय प्रयोग के अनुपात 56 तथा 43 प्रतिशत थे तो शहरी क्षेत्रों में 75 और 72 प्रतिशत। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्वच्छ भारत के खुले में शौच मुक्त समुदायों की ओर अग्रसर होने में नारी वर्ग एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। यही वर्ग पुरुषों एवं बालकों को भी अपना शौच व्यवहार बदलने की प्रेरणा दे सकता है।

1.107 इस समस्या को सुलझाने की दिशा में पहला कदम समस्या की उपस्थिति को स्वीकार करना है। इसका अर्थ है सामाजिक दृष्टि से वर्जित विषय पर अधिक जानकारी को संकलित एवं संप्रेषित करना होगा। दूसरे यह स्वीकार करना होगा कि स्वच्छता सेवा सुलभ होने पर नारी के व्यवहार में बहुत शीघ्र सकारात्मक परिवर्तन

रेखाचित्र 24 : महिलाओं द्वारा शौचालयों का प्रयोग



स्रोत: त्वरित सर्वेक्षण (2016)

आना एक निर्णायक विकास होता है। यही नहीं, इन सुविधाओं के अभाव में नारी वर्ग में गंभीर असुरक्षा की भावना के साथ-साथ पोषण हानि भी घर कर जाती है। इन्हीं कारणों से पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं, पेयजल, सुरक्षा और स्वस्थतापूर्ण व्यवहार, जो स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य हैं- अधिक व्यापक स्तर पर एकांत के मूल अधिकार के अंग के रूप में एक गंभीर नीतिगत सरोकार का रूप धारण कर रहे हैं।

(छ) भारत का शीघ्र ही धूमिल पड़ जाने वाला जनांकीय लाभांश

1.108 विश्व के जनांकीय रूझानों में वर्ष 2016 एक दिग्वर्तन बिंदु रहा है। वर्ष 1950 के बाद इस वर्ष पहली बार विकसित देशों की कार्य आयु (WA) जनसंख्या (15-59 वर्ष का वय वर्ग) में गिरावट आई है [Ip (2015)]। संयुक्त राष्ट्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दशकों में चीन और रूस में भी WA जनसंख्याओं में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ जाएगी। किन्तु भारत WA जनसंख्या के मामले में अभी एक सुखद स्थिति में प्रतीत होता है। इसी अवधि में यहां तो कार्य करने वाली जनसंख्या के अनुपात में एक तिहाई की वृद्धि होने वाली है। किन्तु ध्यान रहे, जनांकिकी एक सुअवसर प्रदान कर सकती है नियति का निर्धारण नहीं।

1.109 पिछले दो दशकों के आर्थिक शोध ने सुझाया है कि पूर्वी एशिया में संवृद्धि का दौर संभवतः जनांकीय कारकों द्वारा संचालित रहा है (ब्लूम आदि, 2003)। सकल जनसंख्या के अधिक बड़े अनुपात के कार्यरत वर्ग में होने से आर्थिक सक्रियता से देश को अधिक लाभ होते हैं। युवा पीढ़ियां अधिक उद्यमशील होती हैं (यह प्रवृत्ति उत्पादिता वृद्धि में सहायक होती है); ये बचत भी अधिक करती हैं (जिसके सकारात्मक प्रतिस्पर्धा प्रभाव संभव हैं- प्रसाद, राजन और सुब्रमण्यम, 2007; वी और झांग, 2011); और आर्थिक संवृद्धि के कारण इसलिए भी राजकोषीय आधार का विकास होता है कि निर्भर बच्चों और वृद्धजनों की संख्या कम होती है (सरकार को इनकी देखभाल पर कम व्यय करना पड़ता है, देखें ब्लूम आदि 2010)।

1.110 सिद्धांत तो यही सुझाता है कि जनांकीय लाभांश का संचालक विशेष चर WA और NWA जनसंख्या का अनुपात है, यह अनुपात एक होने का अर्थ है कि कार्य

समर्थ एवं निर्भर व्यक्तियों की संख्या एक समान है। WA/NWA अनुपात का स्तर और उसमें संवृद्धि के आर्थिक गतिविधि पर सकारात्मक प्रभाव होते हैं (क्लूम एवं केन्निंग, 2004)।

विशिष्ट भारतीय जनांकिकी

1.111 रेखाचित्र 25 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यम जनसंख्या पूर्वकालनों के आधार पर 1970-2050 की अवधि में भारत, ब्राजील, कोरिया और चीन के WA/NWA जनसंख्या अनुपातों के विकास क्रमों की तुलना की जा रही है। यहां भारत की जनांकिकी संरचना की तीन पृथक-पृथक विशेषताएं स्पष्ट हो रही हैं। इनके पूरे देश एवं इसके विभिन्न प्रांतों के संवृद्धि परिदृश्यों के लिए बड़े निहित अर्थ होंगे।

1.112 एक तो भारत का जनांकिकी चक्र अन्य देशों से 10-30 वर्ष पीछे चल रहा है, अब यह अगले कुछ दशकों में उन देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तरों को छू लेने का एक सुअवसर प्रदान कर रहा है।

1.113 साथ ही भारत के WA/NWA जनसंख्या अनुपात के उच्चतम स्तर के 1.7 तक पहुँचने की आशा है। यह ब्राजील और चीन से बहुत कम रहेगा, क्योंकि उन दो देशों में तो यह अनुपात कम से कम 25 वर्षों तक 1.7 बना रहा था। और अन्त में, भारत का यह अनुपात इस शीर्ष स्तर के आसपास अन्य देशों की अपेक्षा अधिक लंबी अवधि तक बने रहने की भी आशा है।

1.114 इस विशिष्ट स्वरूप का एक कारण भी है और संभावित परिणाम भी। कारण तो रेखाचित्र 26क में तुलनीय देशों और देश समूहों के सकल गर्भाधान दरों (TFR) के रेखांकन से स्पष्ट हो जाता है। यह चित्र दर्शाता है कि इन देशों ने भी अपनी द्वितीय महायुद्ध पश्चात् यात्रा लगभग उतनी ही ऊँची TFR दर से प्रारंभ की थी। चीन और कोरिया में यह दर शीघ्र ही पुनर्स्थापन दर से कम रह गई, अर्थात् प्रति नारी दो से कम बच्चे। इससे 2000 के प्रारंभिक वर्षों तक WA अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई, किन्तु फिर वृद्धता का संचार प्रारंभ हो गया। भारत में, उनके विपरीत TFR में गिरावट काफी धीमी रही है।

1.115 संवृद्धि प्रभाव कुछ इस प्रकार है। भारत को पूर्व एशियाई देशों की भांति संवृद्धि दरों में उच्चावचन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कम से कम जनांकिकी लाभांश के कारण तो ऐसा नहीं हो पाएगा। किन्तु अन्य कारणों से संवृद्धि दर में तेजी अवश्य आ सकती है। ये कारण सुधारों और आन्तरिक संस्थागत सामर्थ्य से जुड़े हैं। हां, भारत जनांकिकी लाभांश के फलस्वरूप तीव्र आर्थिक संवृद्धि को अधिक लम्बी अवधि तक जारी रखने में अवश्य सफल हो सकेगा।

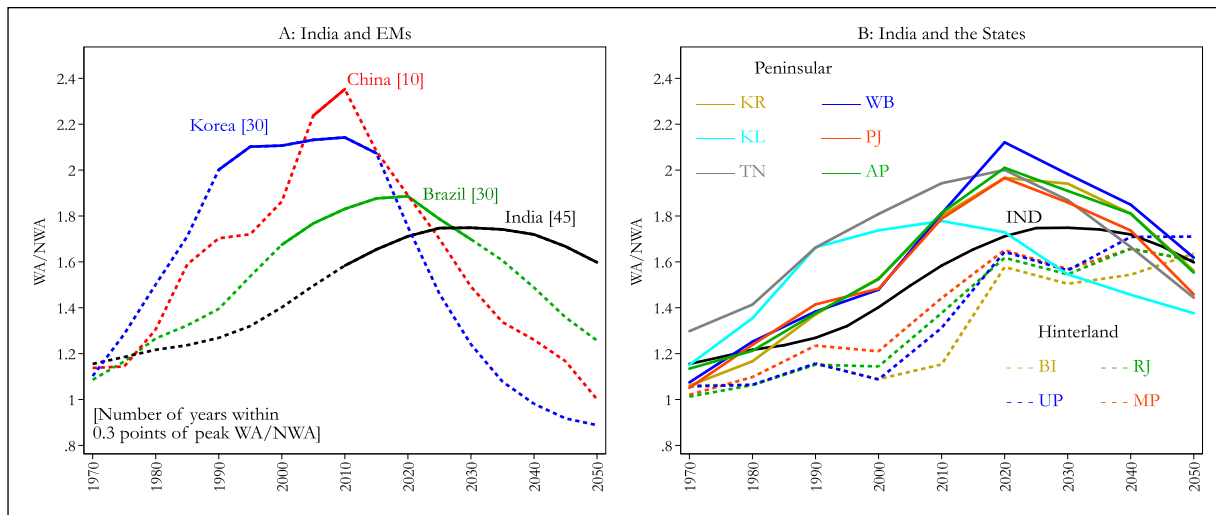
1.116 भारत की एक विशेषता उसके प्रांतों में विद्यमान व्यापक विषमता है। उनकी जनांकिकी रचनाओं तथा विकासक्रमों में बहुत विविधताएं हैं। रेखाचित्र 25(ख) में 10 भारतीय राज्यों की कार्य आयु जनसंख्या का विकास क्रम दिखाया गया है, इसकी तुलना रेखाचित्र 25क में दिखाए गए अन्य उदीप्यमान बाजार व्यवस्थाओं के विकासक्रमों के साथ अवश्य करनी चाहिए।¹⁵

1.117 प्रायद्वीप क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, करेल, कर्नाटक, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश) तथा आन्तरिक क्षेत्र (मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार) के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रायःद्वीपीय राज्यों का विकास क्रम चीन और कोरिया के निकट है, यहां WA जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के बाद गिरावट की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। हां, एक अंतर अवश्य है, पूर्वी देशों की अपेक्षा इन प्रांतों में WA जनसंख्या अनुपात का शीर्षस्तर कम ही रहेगा (पश्चिम बंगाल अपनी अतिनिम्न TFR के कारण कोरिया के निकटस्थ दिखाई दे रहा है)। इसके विरीत आन्तरिक प्रांतीय क्षेत्र WA जनसंख्यानुपात में चल रही वृद्धि के कारण अभी और आगे तक युवा एवं गत्यात्मक बना रहेगा, इसका शीर्ष स्तर तो वर्तमान शताब्दी के मध्य में ही आ जाएगा।

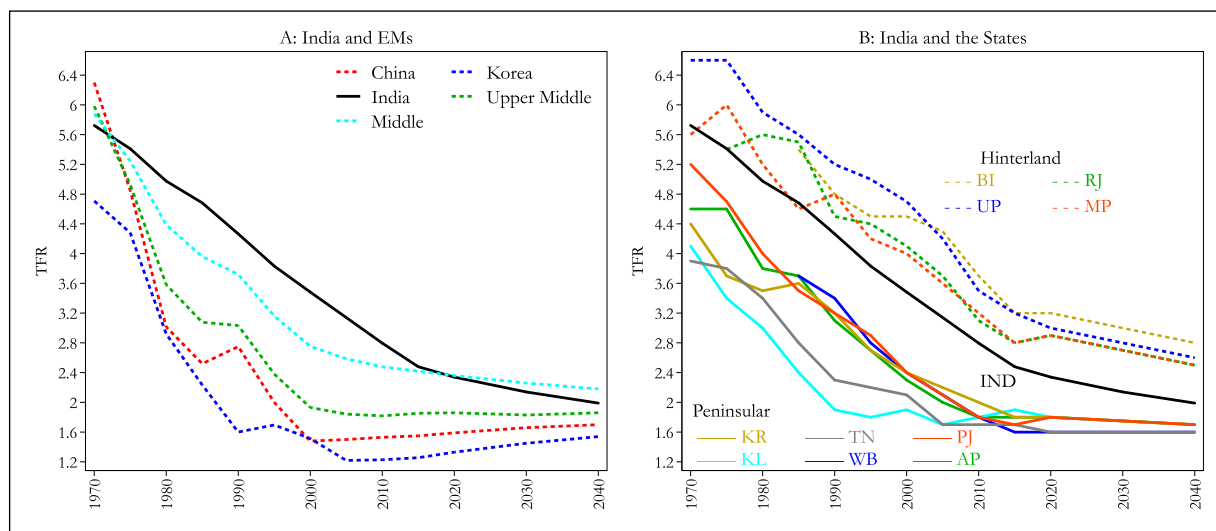
1.118 प्रायःद्वीपीय एवं आन्तरिक प्रांतों के बीच यह विभाजन मूलतः उनके TFR के स्तरों के कारण है (देखें रेखाचित्र 26क यह 26ख का TFR प्रतिरूप है)। जनांकिकी दृष्टि से एक नहीं दो भारत हैं, उनके नीतिगत सरोकार भी अलग-अलग होंगे। एक भारत वह है जहां शीघ्र ही वृद्धता का संचार प्रारंभ हो जाएगा, वहां वृद्धजन

¹⁵ नवीनतम गर्भाधान और मृत्युदरों पर आधारित प्रांतवार जनांकिकी पूर्वकालन (2011-2050) प्रो. एस इरुडिया राजन और डॉ. एस सुनीता, सेंटर फॉर डिवेलपमेंट स्टडीज, केरल ने किया है।

रेखाचित्र 25 : कार्यशील एवं गैर कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WA/NWA)



रेखाचित्र 26 : भारत में TFR में धीमी गिरावट : एक दौ-धारी तलवार



स्रोत: भाग (क) : UN World Population Prospects (2015)

भाग (ख) : भारत की जनगणना पर आधारित
प्रौ. इरुदया राजन (CDS, केरल) का अध्ययन (रेखाचित्र 28, 29)

समाज और उसकी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देना आवश्यकता होगा। दूसरा वह भारत है जो युवा है, वहां तो शिक्षा, कौशल प्रदान करना आवश्यक होगा, साथ ही रोजगार के अवसरों के सृजन पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। हां, देश के भीतर विद्यमान विविधताएं किसी सीमा तक अधिक श्रम गतिशीलता के माध्यम से इन सरोकारों का समाधान पाने में सहायक हो सकती हैं। उससे जनांकीय असंतुलन का भी निवारण होगा।

संवृद्धि प्रभाव

1.119 इस जनांकीय प्रतिरूप के संवृद्धि पर दो

महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। एक तो लगता है कि भारत के लिए जनांकीय लाभांश का शीर्ष स्तर शीघ्र ही आने वाला है। रेखाचित्र 26 'क' के अनुसार समस्त भारत के लिए यह शीर्ष स्तर 2020 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में ही आ जाएगा। किन्तु रेखाचित्र 26 'ख' बता रहा है कि यह प्रायः द्वीपीय क्षेत्र में 2020 में तो आन्तरिक क्षेत्र में 2040 के आसपास संभव होगा।

1.120 मोदी और अय्यर (2011) की विश्लेषण विधि पर आधारित तालिका-3 ने पिछले एवं आगामी चार दशकों के लिए भारत के जनांकीय लाभांश का आंकलन किया है (अर्थात् यह आंकलित किया है कि केवल

जनांकीय कारणों से कितनी अतिरिक्त संवृद्धि संभव हुई है)। यहां आंकड़े 2011-20 की अवधि में अपना शीर्ष स्तर 2.6 प्राप्त कर आगे घटते दिखाई देते हैं। संवृद्धि में अतिरिक्त उछाल का स्तर 2020 के दशक में 1.8 प्रतिशत बिन्दु रहने की अपेक्षा है। दूसरे शब्दों में, भारत अगले चार वर्षों में ही अपने उच्चतम जनांकीय लाभांश को प्राप्त कर चुका होगा। किन्तु ध्यान रहे, इससे आगे यह लाभांश ऋणात्मक नहीं हो जाएगा, केवल इसके सकारात्मक प्रभाव कुछ धीमे होने लगेंगे।

तालिका 3 : भारत के लिए पूर्वाकलित जनांकीय लाभांश

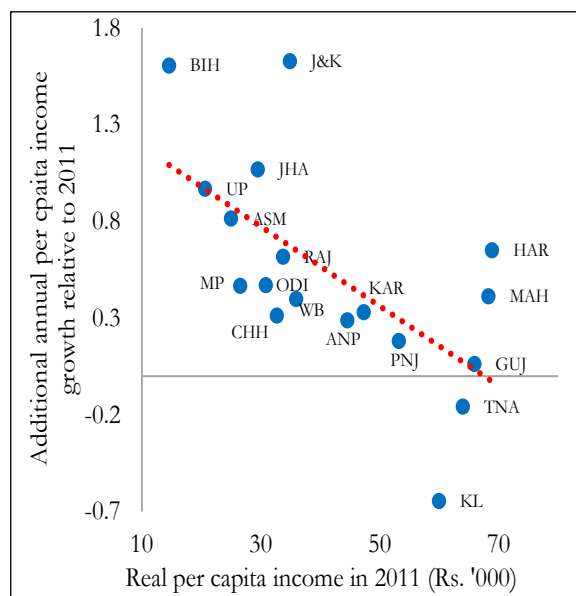
दशक	जनांकीय लाभांश के कारण प्रतिव्यक्ति आय में अतिरिक्त वृद्धि	WA/NWA (WA कुल जनसंख्या) दशक के आरंभ में
2001-10	1.44	1.33 (57.1)
2011-20	2.62	1.53 (60.5)
2021-30	1.81	1.81 (64.4)
2031-40	1.92	1.72 (63.2)
2041-50	1.37	1.72 (63.3)

स्रोत: समीक्षा की गणनाएं

1.121 संवृद्धि पर प्रभाव का दूसरा प्रभाव देश भर में वितरण-आवंटन से संबंधित है। इसकी एक विधि तो राज्यों के स्तरों पर अतिरिक्त संवृद्धियों की वर्तमान प्रतिव्यक्ति जीडीपी से तुलना है। रेखाचित्र 27 में इन्हीं दो चरों को अंकित किया गया है। यहां सबसे अच्छा समाचार यही है कि इनके बीच ऋणात्मक संबंध स्पष्ट हो रहा है। दूसरे शब्दों में, अपेक्षाकृत गरीब प्रांतों को भविष्य में जनांकीय लाभांश की प्राप्ति होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप, देश भर में आय के स्तरों में एक अभिसृति दिखाई देगी।

1.122 इस आशाजनक दृश्यांकन में भी बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र धनात्मक “बहिष्प्रायी” प्रतीत होते हैं अर्थात् इनकी वर्तमान आय की तुलना में भविष्य में इनका जनांकीय लाभांश कहीं उच्चतर होगा। इस अतिरिक्त लाभांश के फलस्वरूप जहां बिहार अन्य प्रांतों के निकट पहुँचेगा वहीं पहले से ही समृद्ध

रेखाचित्र 27 : प्रतिव्यक्ति आय 2011 और जनांकीय लाभांश (2011-31)¹⁶



स्रोत : समीक्षा की गणनाएं

हरियाणा और महाराष्ट्र भारत की औसत से कहीं ज्यादा दूर छलांग लगा जाएंगे। दूसरी ओर केरल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ऋणात्मक बहिष्प्रायी है, इनके जनांकीय लाभांश वर्तमान आय स्तर से कम रहेंगे। परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत गरीब प्रांत और पिछड़ जाएंगे, अपेक्षाकृत समृद्ध केरल भी औसत स्तर की ओर अग्रसर हो जाएगा, इसकी संवृद्धि दर को उत्साह प्रदान करने वाले कारक तेजी से शिथिल हो रहे हैं। इन सबसे केवल एक ही स्थिति में बचा जा सकता है : सुधार और संवृद्धि की प्रक्रियाओं को और अधिक बल प्रदान किया जाए।

1.123 भारत में जनांकीय लाभांश प्रेरित संवृद्धि क्रम अगले पांच वर्षों में अपने शीर्ष स्तर को छूने वाला है, क्योंकि देश का कार्यवय जनसंख्या अनुपात अब उच्चतर स्तर को पा रहा है। किन्तु इस अनुपात में कमी का क्रम बहुत धीमा रहेगा, इसी कारण भारत को पूर्वी एशिया की भांति संवृद्धि में तीव्र गिरावट का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, प्रायः द्वीपीय एवं आन्तरिक प्रांतों में विशाल जनांकीय अन्तर भी इन क्षेत्रों के उस शिखर स्तर को पाने के समय में भारी अन्तर ला सकते हैं।

¹⁶ यह माना है कि प्रत्येक राज्य को WA/NWA में वृद्धि से उतना ही जनांकीय लाभांश मिलता है जितना औसत स्तर पर पूरे भारत को मिलता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता असत्य भी हो सकती है, क्योंकि लाभांश का वास्तविक स्तर तो प्रशासन, राज्य स्तर पर नीति परिवेश तथा विभिन्न राज्यों के बीच प्रवसन पर निर्भर होगा।

यही नहीं इनके कारण श्रम की गतिशीलता के माध्यम से जनांकी असंतुलन का भी निवारण संभव है (देखें अध्याय-12)। किन्तु शीघ्र ही विलुप्त होने की आशंका से ग्रस्त इस जनांकीय लाभांश को अधिकतम करने के लिए तुरंत आवश्यक सुधार लागू करने की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता।

संदर्भ

1. Aiyar, Shekhar, and AshokaMody. "The Demographic Dividend: Evidence from the Indian States." *India Policy Forum*. No. Volume 9. National Council of Applied Economic Research, 2013.
2. Bloom, David E., David Canning, and Jaypee Sevilla. "The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change. Rand Corporation, 2003.
2. Bloom, David E., and David Canning. "Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance." *Population and Development Review* 34 (2008): 17-51.
3. Bloom, David E., David Canning, and Günther Fink. "Implications of population ageing for economic growth." *Oxford review of economic policy* 26.4 (2010): 583-612.
4. Coffey Diane, Gupta Aashish, Hathi Payal, Spears, D., Srivastav Nikhil, Vyas Sangita (2016). *Understanding Open Defecation in Rural India*, EPW
5. Curtis C. and Minjas J (1985). *Expanded Polysterene for mosquito control. Parasitology Today* 1, 36.
6. Ip, Greg. "How Demographics Rule the Global Economy." *Wall Street Journal*. Nov. 22, 2015 [<http://www.wsj.com/articles/how-demographics-rule-the-global-economy-1448203724>, accessed: 11:08 am, January 23, 2016]
7. National Sample Survey Organization (NSSO). 2016. *Swachhata Status Report*. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt of India.
8. Prasad, Eswar S., Raghuram G. Rajan, and Arvind Subramanian. "Foreign Capital and Economic Growth." *Brookings Papers on Economic Activity* 1.2007-1 (2007): 153-230.
9. Singh, J, Bhoi S, Gupta V, Goel A (2008). *Clinical Profile of Venomous Snake Bites in a North Indian Military Hospital. Journal of Emergencies, Trauma, and Shock* 1, 78-80.
10. Spears, D., Ghosh, A., Cumming, O. (2013). *Open Defecation and Childhood Stunting in India: An Ecological Analysis of New Data from 112 District*
11. Wei, Shang-Jin, and Xiaobo Zhang. "The competitive saving motive: Evidence from rising sex ratios and savings rates in China." *Journal of political Economy* 119.3 (2011): 511-564.

परिशिष्ट I : वैकल्पिक विनिमय दरों के सूचकांक के लिए करेंसी भारमान

क्र. सं.	देश	IMF 25 देश	RBI 36 करेंसियां	Asia-H 30 देश	Asia-M देश 30
		25 देश	36 देश	30 देश	30 देश
1	संयुक्त राज्य	17.82	8.80	7.86	11.44
2	चीन	12.47	10.84	43.51	31.12
3	जर्मनी	9.08		3.36	5.04
4	जापान	6.13	2.72	2.10	3.15
5	ब्रिटेन	5.58	2.36	2.60	3.52
6	फ्रांस	4.63		1.61	1.96
7	बेल्जियम	4.53		2.64	3.95
8	इटली	4.33		1.39	2.09
9	कोरिया	4.26	2.65	2.26	3.39
10	सिंगापुर	3.53	3.37	2.30	3.45
11	संयुक्त अरब अमीरात	2.84	11.44		
12	आस्ट्रेलिया	2.47	2.36		
13	नीदरलैंड	2.39		0.94	1.41
14	कनाडा	2.20	0.69		
15	स्पेन	2.12			
16	ताइवान	1.96	1.18	0.83	1.24
17	मलेशिया	1.90	2.07	1.12	1.68
18	रूसी संघ	1.85	0.97	1.12	1.46
19	थाइलैंड	1.70	1.28	1.18	1.77
20	इंडोनेशिया	1.51	3.02	0.71	1.06
21	स्वीटजरलैंड	1.42	4.80	0.70	0.94
22	ब्राजील	1.41	1.51		
23	स्वीडन	1.34	0.40		
24	इजराइल	1.28	0.95	0.77	1.16
25	तुर्की	1.26	0.69	0.96	1.01
26	साऊदी अरब		5.51	1.93	1.94
27	हांगकांग		3.41	4.01	5.63
28	कुवैत		2.52		
29	नाइजीरिया		2.49		
30	ईरान		2.38	0.55	0.82
31	दक्षिण अफ्रीका		2.08	0.57	0.86
32	कतर		1.89		
33	वियतनाम		0.81	5.80	3.36
34	मिश्र		0.75		
35	श्रीलंका		0.74	0.56	0.85
36	बंगलादेश		0.73	1.21	1.09
37	मैक्सिको		0.58	4.45	2.57

क्र. सं.	देश	IMF 25 देश	RBI 36 करेंसियां	Asia-H 30 देश	Asia-M देश 30
		25 देश	36 देश	30 देश	30 देश
38	केनिया		0.45		
39	पाकिस्तान		0.36		
40	अर्जेंटीना		0.25		
41	फीलिपीन्स		0.24	1.36	0.88
42	पोलैंड			0.90	0.64
43	चैक गणराज्य			0.71	0.51
	यूरो क्षेत्र	27.08	12.69	11.56	15.62
	कुल भार	100.01	99.98	100.00	100.00
	शीर्ष 20 करेंसियां	93.30	88.91	92.76	91.33

ASIA-H (ASIA-M) उन कल्पनिक समुच्चयों को दर्शा रहे हैं जहां एशियाई देशों को अन्य दो सूचकों की अपेक्षा अधिक उच्च सामान्य अधिक मान दिया गया है। प्रत्येक भारमान विधि में तीन शीर्ष करेंसियों को गहरे छापा गया है।

इन भार मानों का निर्धारण कैसे करते हैं? हम प्रत्येक व्यापारिक भागीदार के लिए दो भार लेते हैं : पहला भार तो भारत के विनिर्मित आयात में उस देश का वास्तविक अंश (W1) है; दूसरा भार आंकलित करने के लिए उन देशों पर ध्यान दिया जाता है, जिन्होंने 2010-15 की अवधि में विश्व विनिर्मित निर्यात में अपना अंश बढ़ाने में सफलता पाई है। यह UNCTAD के आंकड़ों पर आधारित है। ऐसे प्रत्येक देश की वृद्धि का शेष सभी देशों की वृद्धि से अनुपास W2 आंकलित किया जाता है। अतः, उदाहरण के लिए यदि 10 देशों ने कुल मिलाकर अपना निर्यात अंश 10 प्रतिशत बढ़ाया हो जिसमें चीन की 4 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि भी शामिल है तो चीन का अंश 0.4 होगा। इसी प्रकार अन्य देशों के भार आंकलित होते हैं। ASIA-H में हमें W1 और W2 को समान भार प्रदान करते हैं, किन्तु ASIA-M में इनके भार क्रमशः 0.75 और 0.25 रखे जाते हैं।

परिशिष्ट-II स्वच्छता सर्वेक्षण का विवरण

प्रतिदर्श का आकार : त्वरित अध्ययन के प्रतिदर्श में जीवन चक्र भर में फैले हुए संवादी थे :

- किशोरियां (10-19 वर्ष वर्ग)
- गर्भवती महिलाएं
- 0-60 माह की आयु के बच्चों वाली महिलाएं

तुलना करने के लिए इन्हीं परिवारों के एक उपप्रतिदर्श के पुरुषों को भी सम्मिलित कर लिया गया था।

सर्वेक्षण के लिए देश को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था : उच्चतम IHHL प्रसार; उच्च IHHL प्रसार; मध्यम IHHL प्रसार; निम्न IHHL प्रसार और निम्नतम IHHL प्रसार। प्रत्येक क्षेत्र से दो राज्य चुने गए। एक उच्च प्रदर्शन वाला दूसरा निम्न निष्पादन वाला। प्रत्येक राज्य से 2 जनपद, प्रत्येक जनपद से 12 प्राथमिक सर्वे इकाईयां और प्रत्येक PSU से 18 परिवार चुने गए। कुल मिलाकर 4320 परिवारों का प्रतिदर्श बना, जिसमें 4255 महिलाएं और 1450 पुरुष मिलकर 5705 का आकार बनाते थे। प्रांत और जनपदों का चयन IHHL प्रसार के आधार पर हुआ। प्रत्येक क्षेत्र से उच्च एवं निम्न निष्पादक राज्य चुना गया यही कसोटी राज्य से जनपद चुनने में प्रयोग की गई। 18 संवादियों का चयन प्रत्येक प्रतिदर्श Use से यादृच्छिक विधि से किया गया, वे तीनों संवाद वर्गों में समान रूप से विभाजित थे। एक त्रुटि यही है कि इसे संपूर्ण रूप से प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं कह सकते।